पृष्ठ- 36 रुपये-40

RNI : UPBIL/2017/73686

टाइम्स एण्ड स्पेस

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

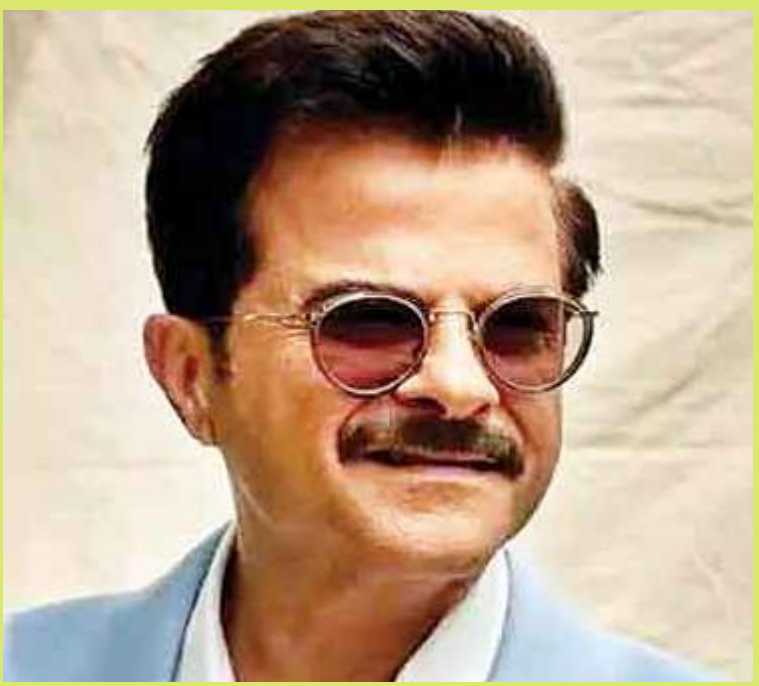

हिमाँशु श्रीवास्तव (प्रकाशक)

राहुल त्यागी (मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

गिरजेश कुमार श्रीवास्तव (उप सम्पादक)

कंचन श्रीवास्तव (उप सम्पादक)

प्रशान्त कुमार तिवारी (उप सम्पादक)

कु० मनीष सिंह सेंगर (उप सम्पादक)

संजय अवस्थी
(ब्यूरो चीफ, लखनऊ)

अशरफ जमाल
(ब्यूरो चीफ, कानपुर)

अमित कुमार श्रीवास्तव
(ब्यूरो चीफ, उन्नाव)

मनोज श्रीवास्तव
(ब्यूरो चीफ, दिल्ली)

मुकेश कुमार श्रीवास्तव
(ब्यूरो चीफ, जयपुर)

प्रताप नारायण राव
(ब्यूरो चीफ, वाराणसी)

स्मृति यादव
(ब्यूरो चीफ, भोपाल)

अंशुमाली सिन्हा
(ब्यूरो चीफ, बरेली)

हिन्दी मासिक RNI : UPBIL/2017/73686

टाइम्स एण्ड स्पेस

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

वर्ष 07 सितम्बर 2023 अंक-07

Times and Space

प्रकाशक

हिमाँशु श्रीवास्तव

मो० 9918558866

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

राहुल त्यागी

मो० 9005199788

उप सम्पादक

गिरजेश कुमार श्रीवास्तव

कंचन श्रीवास्तव

प्रशान्त कुमार तिवारी

कु० मनीष सिंह सेंगर

ब्यूरो चीफ

संजय अवस्थी (लखनऊ)

अशरफ जमाल (कानपुर)

डॉ० शशिवेन्द्र सिंह (कानपुर देहात)

अमित कुमार श्रीवास्तव (उन्नाव)

मनोज श्रीवास्तव (दिल्ली)

मुकेश कुमार श्रीवास्तव (जयपुर)

प्रताप नारायण राव (वाराणसी)

स्मृति यादव (भोपाल)

अंशुमाली सिन्हा (बरेली)

समस्त पदाधिकारी एवं लेखक अवैतानिक है एवं समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय में सम्बद्ध होंगे।

इस अंक में प्रकाशित लेखों एवं समाचारों का समस्त उत्तरदायित्व लेखकों का है। विचारों व लेखों से प्रकाशक व सम्पादकों का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Mob. 9918558866,7388011011,
8931091821, 8429098886
E-mail : timesandspace.com@gmail.com
website: www.timesandspace.com

(सभी पद अवैतनिक हैं)

इस अंक में

(1) निणयों पर कानूनी बाध्यता नहीं है, इसलिए अप्रभावी नजर 5
(2) अमृतकाल का सुनहरा पक्ष है मातृभाषा.....6
(3) भारत में मातृभाषाओं का संकट- चुनौतियों और समाधान 7
(4) सनातन धर्म पर हमला करने के लिए अचानक से इतने सारे 8
(5) नरेंद्र मोदी ने बढ़ाई दुनिया में भारत की साख और धाक.....10
(6) कुछ लोग जिंदगी में खुद कुछ करने की बजाय दूसरों की.....11
(7) सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी सदस्य देश स्वभाषा का 12
(8) अदालतों से मिलने वाली लताड़ की अब ममता सरकार को 13
(9) बसपा अकेले के चक्कर में वोटकटआ पार्टी बनकर न रह.....14
(10) ऋषि सुनक का भारत में दामाद जैसा स्वागत भारतीय 15
(11) सनातन और हिंदू संस्कृति का विरोधी साबित..... 16
(12) व्यावसायिक वाहनों की बिक्री में तेजी देश में 18
(13) आरक्षण देने भर से महिलाओं की स्थिति नहीं सुधर.....19
(14) आगामी लोकसभा चुनावों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है.....20
(15) बुंदेलखंड के बुंदेला परिवार का नया राजनीतिक दाँव 21
(16) नये भारत के निर्माता हैं कर्मयोद्धा और प्रधान 22
(17) एक नहीं कई टुकड़ों में बँटेगा पाकिस्तान, आतंकवाद का 24
(18) बुलन्द भारत की बुलन्द आवाज.....25
(19) भारत-मध्यपूर्व-यूरोप इकॉनमी कॉरिडोर के आर्थिक, ... 27
(20) पार्टी बदलना है.....29
(21) पहाड़ों पर है घूमने का मन तो चले आइए भोपाल, नेचर 30
(22) 43 वर्ष की हुईं करीना कपूर.....31
(23) झक्कास-बोलने से पहले लेनी पड़ेगी अनिल कपूर की 32
(24) सिखों के पहले गुरु थे नानक देव, समाजिक कुरीतियों 31
(25) 22 साल बाद फिर से रिलीज होगी गदर- एक प्रेम कथा 33
(26) औद्योगिक विकास के समर्थक थे सर 34

Times and Space

स्वामी, प्रकाशक एवं सम्पादक हिमांशु श्रीवास्तव द्वारा ज्ञानोदय प्रिंटर्स, त्रिमूर्ति मंदिर परिसर, गांधी ग्राम जी०टी० रोड, कानपुर-208007 से मुद्रित एवं 53 रैना मार्केट, वीआईपी रोड, कानपुर नगर-208002 से प्रकाशित

भारत का जी-20

राजधानी नई दिल्ली 'अभेद्य दुर्ग' बनी है और दुल्हन की तरह सजी-धजी भी है। भारत के लिए ये ऐतिहासिक क्षण हैं। जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन का शंखनाद आज होना है। लगभग सभी राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री भारत के आंगन में पहुंच चुके हैं। अमरीकी राष्ट्रपति के तौर पर जोसेफ बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक पहली बार भारत आए हैं। करीब 10,000 विदेशी मेहमान भारतीय आतिथ्य का आनंद लेंगे। मोटे अनाज के पकवान और मिष्ठान्नों का लुत्फ उठाएंगे। जी-20 महज एक भू-राजनीतिक और आर्थिक विकास का मंच नहीं है। यह ऐसा जी-20 सम्मेलन है, जिससे भारत 'विश्व-मित्रों' की जमात में आ गया है। अब वैश्विक नेताओं के सामने भारत की क्षमता, ताकत और सांस्कृतिक विरासत के अध्याय खुले हैं। वे आकलन और विश्लेषण कर सकते हैं। भारत ने अपने विदेशी अतिथियों का स्वागत सांस्कृतिक विनम्रता के साथ किया है। हमारे देवी-देवताओं के कल्पना-चित्र, प्राणी-संसार, कलाकृतियां, सांस्कृतिक धरोहरों, नृत्य, झरने और सभास्थल 'भारत मंडपम' के प्रवेश-द्वार पर भगवान नटराज की अद्भुत प्रतिमा की उपस्थिति बेहद कलात्मक लगती है। भारत के रोम-रोम में कला, संस्कृति और संस्कार बसे हैं। नई दिल्ली किसी विशाल बाग में बसा शहर लग रही है। जमीन से आसमान तक ऐसे सुरक्षा-घेरे तैनात किए गए हैं, जो 'चक्रव्यूह' का एहसास कराते हैं।

हमारे प्रिय अतिथियों को पल भर की बेचैनी, असुरक्षा, असुविधा न हो, लिहाजा राफेल, मिराज सरीखे लड़ाकू विमान, कम दूरी की मिसाइलें, एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और जासूस हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। जमीन पर करीब 1.30 लाख पुलिसकर्मी, अर्द्धसैनिक बलों के जवान, सैनिक और कमांडोज को देखकर लगता है मानो भारत किसी 'युद्धक्षेत्र' में मौजूद है। बहरहाल जी-20 शिखर सम्मेलन से यह भ्रम टूटता दिखाई देगा कि यह सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है, क्योंकि अपनी अध्यक्षता में भारत का आग्रह है कि आर्थिक विकास में पिछड़े 'अफ्रीकी संघ' को भी जी-20 में शामिल किया जाए। विकसित, विकासशील और तीसरी दुनिया के एक साथ, एक मंच पर आने से विकास को समग्रता मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी का विचार और संकल्प है कि अर्थव्यवस्था जीडीपी के बजाय मानव-केंद्रित होनी चाहिए, तभी वैश्विक विकास और भाईचारा संभव है। अमरीकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत के संकल्प को ही 'जी-20 का विजन' स्वीकार किया है। वैश्विक राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और विशेषज्ञ जिस एजेंडे पर विमर्श करेंगे, उसमें खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा-संकट और स्वच्छ ऊर्जा, विश्व-व्यवस्था, विकास, जलवायु परिवर्तन, महामारी, रोजगार, सप्लाई चेन, आतंकवाद, हरित पर्यटन, ग्लोबल साउथ, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि मुद्दे महत्त्वपूर्ण हैं। दरअसल यह एजेंडा भारत ने ही तैयार किया है, जिस पर जी-20 के मंच पर विमर्श किया जाएगा। यह भारत का ही जी-20 है, क्योंकि यह सम्मेलन भारत की चौतरफा समृद्धि का सत्यापन भी है। यह आकलन भी सामने आया है कि विमर्श के दौरान सभी देश 200 अरब डॉलर के आपसी कारोबार और औद्योगिक समन्वय का लक्ष्य तय करेंगे। अब भी दुनिया का करीब 75 फीसदी व्यापार जी-20 के देश ही करते हैं।

भारत का विश्व-मंच पर उभार भी बढ़ेगा। ताकतवर देशों के साथ हमारी साझेदारी बढ़ेगी, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत को गढ़ बना कर अपने प्लांट शुरू करेंगी। उत्पादन यहीं होगा, तो रोजगार भी यहीं बढ़ेगा। अमरीका भारत में 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की ओर बढ़ रहा है। प्रीडेटर ड्रोन के खरीदने और भारत में ही उसका उत्पादन-केंद्र बनाने की बात अंतिम दौर में है। इसरो और नासा मिलकर रणनीतिक फ्रेमवर्क और मिशन तय करेंगे। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई और देशों के भारत के साथ काम करने के अपने-अपने लक्ष्य हैं। गौरतलब यह है कि भारत जनवरी, 2024 के 'गणतंत्र दिवस' के मौके पर अमरीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सरीखे 'क्वाड' के साथी देशों को आमंत्रित करना चाहता है, ताकि चीन को कड़ा संदेश दिया जा सके।

निर्णयों पर कानूनी बाध्यता नहीं है, इसलिए अप्रभावी नजर आता है जी-20

योगेंद्र योगी

द्विपक्षीय समझौतों को छोड़ कर सामूहिक तौर पर जी-20 के सदस्यों पर कोई बाध्यता नहीं है कि वो जी-20 के मंच पर किए अपने किए वादों को निभाएं ही। जी-20 के पास भी ऐसा कोई साधन नहीं है, जिसके तहत इन वादों को लागू करने के लिए कुछ किया जा सके। जी-20 की अब तक कि सबसे बड़ी उपलब्धि साल 2008 के आर्थिक संकट को मैनेज करना था। तब आर्थिक संकट को काबू करने में इस समूह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं जी-20 ने आईएमएफ़ और वर्ल्ड बैंक में कुछ सार्थक बदलाव भी किए। इसके बावजूद जलवायु परिवर्तन जैसे मसले हैं जिन पर पेरिस समझौते के बाद भी कुछ नहीं हुआ। जिस तरह यूनाइटेड नेशन्स में बातचीत होती है लेकिन उनके पास धन है जिसका इस्तेमाल कुछ मामलों में किया जा सकता है। जी-20 में ऐसा नहीं है।

ऊपर से देखें तो जी-20 की बैठक में खूब तड़क-भड़क नजर आती है। 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के प्रमुखों का जुटना, एजेंडा तय करना लेकिन गहराई से देखें तो अभी तक जी-20 से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इस तरह के आर्थिक प्लेटफॉर्म तभी ज़्यादा कामयाब होते हैं जब दुनिया में भूराजनीतिक तनाव कम हों। अभी ऐसी स्थिति है कि ये तनाव बहुत ज़्यादा हावी हैं। बड़ी शक्तियां आपस में एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें साथ लाना बड़ी चुनौती होती जा रही है। वैश्विक तनाव का प्रभाव केवल जी-20 पर हुआ है, ऐसा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी डेडलॉक है क्योंकि रूस-चीन एक तरफ़ हैं और पश्चिमी देश एक तरफ़ हैं। कोविड के समय विश्व स्वास्थ्य संगठन ने काम नहीं किया क्योंकि चीन ने वहां अड़ंगे लगाए। डब्ल्यूटीओ काम नहीं कर रहा। जी-20 एक नया संगठन है, जिसमें आर्थिक हालातों को सुधारने की बात की गई है, लेकिन इसका कोई ख़ास असर विश्व पर नहीं हुआ। 1999 में गठन के बाद से समूह के अधिकांश साझे बयान बस बयान तक ही सीमित रह गए। जैसे रोम में साल 2021 शिखर सम्मेलन के

दौरान जी20 नेताओं ने कहा था कि वे सार्थक और प्रभावी कार्यों के साथ ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करेंगे, विदेशों में कोयला बिजली संयंत्रों के वित्तपोषण को समाप्त करेंगे। बाद में साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बताया कि दुनिया भर में कोयला आधारित बिजली उत्पादन एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। कोयले में निवेश 10 प्रतिशत बढ़कर 150 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। इससे कार्बनजनित प्रदूषण में बढ़ोत्तरी हुई है।

मई में हिरोशिमा में जी7 नेताओं द्वारा निरंतर जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में तेजी लाने पर सहमति जताने के बावजूद जी20 की ओर से रोडमैप पर सहमति नहीं बन पाई। वर्ष 2021 में, जी-20 ने एक बड़े टैक्स सुधार का समर्थन किया जिसमें प्रत्येक देश के लिए कम से कम 15 प्रतिशत का वैश्विक न्यूनतम कर शामिल था। इसने नए नियमों का भी समर्थन किया जिसके तहत अमेजन जैसे बड़े वैश्विक व्यवसायों को उन देशों में कर का भुगतान करना होगा जहां उनके उत्पाद बेचे जाते हैं, भले ही वहां उनके कार्यालय न हों।

ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट एक बड़ा कदम था लेकिन ये अब तक लागू नहीं हुआ। साल 1999 से पहले कुछ सालों से एशिया आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिसे देखते हुए जर्मनी में जी8 देशों की बैठक हुई और जी20 का गठन किया गया। इसमें सभी मजबूत अर्थव्यवस्था वाले 20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को बुलाया गया। संगठन का मकसद वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर आपसी चर्चा कर हल निकालना था। साल 2008 की वैश्विक मंदी के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस बैठक में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। जी20 समिट दुनिया के 20 देशों द्वारा मिलकर बनाया गया एक शक्तिशाली ग्रुप है। साल 1999 में इसकी स्थापना की गई। इसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों द्वारा मिलकर आपसी सहयोग के लिए बनाया गया था। इसमें भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका सउदी अरब, तुर्किये, मेक्सिको, साउथ कोरिया, यूरोपीय संघ और अर्जेंटीना शामिल हैं। युरोपियन यूनियन सहित कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन इसके आमंत्रित सदस्य हैं। दिखने में जी-20 बहुत ताकतवर वैश्विक संगठन नजर आता है। इसके सदस्य देशों के पास मिलाकर दुनिया की 80 प्रतिशत जीडीपी, 60 प्रतिशत आबादी और 75 प्रतिशत ग्लोबल ट्रेड है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर डाल सकता है, लेकिन फैसले पर अमल हो इसकी कोई गारन्टी नहीं है। यही वजह है कि जी-20 अपने अस्तित्व में आने के बाद से लेकर अभी तक विश्व को कोई ठोस दिशा नहीं दे सका है। इसके सदस्य देश आपस में द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय आधार पर कोई समझौता अपने देशों के फायदे के लिए बेशक कर लें, किन्तु उसका वैश्विक लाभ मिलता नजर नहीं आता है।

अमृतकाल का सुनहरा पक्ष है मातृभाषा, मगर बच्चों में भाषा संरचना का स्वरूप बिखरता हुआ दिख रहा है

ऋचा सिंह

हमारी भाषा हमारे अपने व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। भाषा वैचारिक आदान-प्रदान का माध्यम है, भाषा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। भाषा हमारे समाज के निर्माण, विकास, अस्मिता, सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान की महत्वपूर्ण साधन है। हम कह सकते हैं कि बिना भाषा के मानव जीवन अपूर्ण है। भाषा का विस्तार एवं विकास मनुष्य का अपना ही विकास है। भाषा ही पारस्परिक ज्ञान, संबंध, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु का कार्य करती है। इसके दोनों लिखित और मौखिक रूप के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। स्वयं को व्यक्त करने की उत्कंठा ने ही हमें व्यक्ति की संज्ञा दे दी, यही वो विशेषता है जिसने हमें सभी प्राणियों में सर्वोच्च स्थान दिया है।

भाषा शिक्षक के रूप में एक शिक्षक अपने छात्रों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रिय होता है। अपनी प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक जिन्होंने हमें पहली बार पढ़ना लिखना सिखाया उन्हें हम कभी नहीं भूल पाते। यूं तो बच्चा अपने घर परिवार तथा आसपास बोली जाने वाली भाषा को सुनकर बोलकर स्वत: ही भाषा सीख लेता है किंतु शुद्ध लिखना और बोलना, भाषा शिक्षण से ही सीखी जा सकती है। जिसमें शिक्षक और विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यालय में ही छात्रों में मौलिक वाक्य संरचना की योग्यता का विकास होता है, जो शुद्ध लिखने बोलने के कौशल से युक्त और संपन्न करता है। इसलिए भाषा शिक्षण में विद्यालय और शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। भाषा ही ज्ञान का आधार है। हर भाषा का अपना स्वभाव होता है, भाषा के इसी स्वभाव को ध्यान में रखकर उसके अपने-अपने आदर्श स्वरूप होते हैं। शिक्षक का कर्तव्य है कि भाषा की भूमिका को समझें और बच्चों को भाषा की भूमिका को समझाएं। जब विद्यार्थी में भाषा के प्रति प्रेम बढ़ता है तब उसे पुष्पित पल्लवित होते देखकर शिक्षक गर्वित हुए बिना नहीं रह पाते। भाषा व्यक्तित्व निर्माण में बहुत सहायक है। पहले बच्चे पढ़ना सीखते हैं और फिर सीखने के लिए पढ़ते हैं। अन्य विषयों के ज्ञान को भाषा ही दिशा प्रदान करती है जिसके लिए प्रारम्भिक कक्षाओं से ही बच्चों को तैयार करने की

आवश्यकता है, हिंदी पढ़ाते हुए बच्चों में मनुजता की दृष्टि विकसित करना मुख्य उदेश्य होना चाहिए। हिंदी पढ़ाने का उद्देश्य ही जीवन को समझना है जो एक सभ्य समाज को खड़ा करता है। भाषा की उपयोगिता के अनेक आयाम हैं। जब बच्चों की अपने भाषा में रुचि बढ़ेगी तब अपनी भाषा के प्रति उन्हें गर्व होगा। यह भाव जब तक एक शिक्षक के रूप में हम बच्चों के अंदर नहीं उपजाएंगे तब तक शिक्षक के रूप में सफल नहीं होंगे और न ही तब तक बच्चे अपने जीवन में भाषा की भूमिका को समझ पाएंगे।

वर्तमान समय में ज्ञान, विज्ञान समुद्र की गहराइयों से लेकर सौरमंडल को अपनी परिधि में निरंतर बांधने का प्रयास कर रहा है। वहीं दूसरी ओर बच्चों में भाषा संरचना का स्वरूप बिखरता हुआ दिख रहा है। जिसमें कसाव लाने की नितांत आवश्यकता है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं जिसमें एक कारण यह भी है कि हम भाषा को सिर्फ विषय के रूप में पढ़ा रहे हैं जबकि बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और अपनी भाषा को इस तरह से देखने की हम भाषा के माध्यम से ही अपने समाज का निर्माण करते हैं अपने समाज को खड़ा करते हैं अपने चारों तरफ एक वातावरण निर्मित करते हैं। ऐसी समझ देने की नितांत आवश्यकता है। आज भाषा को विषय के रूप में पढ़ते हुए उसके वास्तविक स्वरूप उसको पहचाना कर उसको समझने का प्रयत्न छोड़ दिया गया है। जबकि भाषा ही व्यक्तित्व को सजाती, संवारती, आकर्षक और प्रभावशाली बनाती है। हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को भावी जीवन के लिए बाहरी दुनिया से संवाद स्थापित करने के लिए तैयार करें। भाषा की समृद्ध समझ के लिए तैयार करें बच्चों की विचार शक्ति भाषा से ही समृद्ध होती है। शब्द भंडार समृद्धि करना इसे रोचक बनाना बच्चों की भाषा की दक्षता को बढ़ाना है जिसमें मुख्य रूप से बच्चों के प्रारंभिक कक्षाओं के शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

जब एक बच्चा अपनी प्रारंभिक कक्षाओं से ही हिंदी अपनी भाषा को अच्छे से समझता है तो भाषा में अनुशासन, कौशल विकास सरलता सुगमता स्पष्ट और शुद्धता के व्यावहारिक विश्लेषण के साथ ही अपनी भाषा को संगठित और शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के लिए दक्षता हासिल कर लेता है। जो उसके बाहरी समाज से संवाद स्थापित करने में सहायक होता है जो उसके व्यक्तित्व को निखारते हुए उसकी बाहरी दुनिया में और आगे की शिक्षा अर्जन करने के लिए आत्मविश्वास देता है। व्यवहारिक तौर पर देखें तो जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ अशुद्ध शब्द इस तरह से भाषा में समाहित हो गए हैं जिन्हें मानक भाषा से अलग कर पाना कठिन है। इसलिए शिक्षकों का दायित्व है कि बच्चों को भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराए। इस कार्य में शिक्षकों की अहम भूमिका है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति मानवीय संवेदनाओं से जुड़ता है। भाषा ही व्यक्ति को मनुजता में व्यक्त होने का कौशल प्रदान करती है। भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम के साथ ही अनुभूति का भी माध्यम है। जो बोला जा रहा है और जो ग्रहण किया जा रहा है जो समझा जा रहा है क्या उसमें अंतर है यदि अंतर है तो इसका मतलब भाषा ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं किया गया है जब भाषा अभिव्यक्ति के साथ अनुभूत की जाती है और इसकी समझ होगी, भाषा में रचनात्मक का विकास होगा तभी भाषा अपने आप को आदर्श रूप को व्यक्त करेगी भाषा सिर्फ शब्दांकन नहीं है। यह हमारे परिवेश समाज का प्रतिबिंब है जब हम अपनी बात को रखते हैं जब हम अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं तब हम एक समाज का निर्माण करते हैं हम एक समाज को खड़ा करते हैं इसलिए भाषा की जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। एक शिक्षक के तौर पर कक्षाओं में पढ़ते और पढ़ाते वक्त हिंदी शिक्षक के तौर पर हम भाषा को सिर्फ विषय के रूप में ना देखें हम भाषा को एक जीवन की तैयारी के रूप में देखें क्योंकि कक्षाओं में जब बच्चे पढ़ते हैं तो अन्य विषयों को भी पढ़ने के लिए वह भाषा की तैयारी करते हैं।

भारत में मातृभाषाओं का संकट- चुनौतियों और समाधान पर एक नजर

प्रो. संजय द्विवेदी

भाषा का संबंध इतिहास, संस्कृति और परंपराओं से है। भारतीय भाषाओं में अंतर-संवाद की परंपरा बहुत पुरानी है और ऐसा सैंकड़ों वर्षों से होता आ रहा है। यह उस दौर में भी हो रहा था, जब वर्तमान समय में प्रचलित भाषाएं अपने बेहद मूल रूप में थीं। श्रीमद्भगवतगीता में समाहित श्रीकृष्ण का संदेश दुनिया के कोने-कोने में केवल अनेक भाषाओं में हुए उसके अनुवाद की बदौलत ही पहुंचा। उन दिनों अंतर-संवाद की भाषा संस्कृत थी, तो अब यह जिम्मेदारी हिंदी की है। जब हमारे पास एक भाषा होती है, तब हमें अंदाजा नहीं होता, कि उसकी ताकत क्या होती है। लेकिन जब भाषा लुप्त हो जाती है और सदियों के बाद किसी के हाथ वो चीजें चढ़ जाती हैं, तो सबकी चिंता होती है कि आखिर इसमें है क्या? ये लिपि कौन-सी है, भाषा कौन-सी है, सामग्री क्या है, विषय क्या है? आज कहीं पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ मिलता है, तो सालों तक पुरातत्व विभाग उस खोज में लगा रहता है कि लिखा क्या गया है?

भारतीय भाषाओं का बढ़ता प्रभाव

आज भारतीय भाषाओं के बीच संवाद को व्यापक रूप से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। भारतीय भाषाओं में बीच संवाद सैंकड़ों वर्षों से जारी है और इनका विकास भी साथ-साथ ही हुआ है। मसलन बांग्ला और मैथिली में इतनी समानता है कि उनमें अंतर करना मुश्किल है, इसी तरह अवधी और ब्रज भाषा तथा हिंदी और उर्दू में भी ऐसा ही है। हिंदी और उर्दू दैनिकों की भाषा पर हुए एक शोध में देखा गया कि उनमें केवल 23 प्रतिशत शब्द ही अलग थे। हिंदी पत्रकारिता के विकास में मराठी, बांग्ला और दक्षिण भारतीय भाषाओं के योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती। आज पूरे भारत में भारतीय भाषाओं के बढ़ते प्रभाव को देखा जा सकता है। भाषाई पत्रकारिता को हम भारत की आत्मा कह सकते हैं। आज लोग अपनी भाषा के समाचार पत्रों की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए भाषाई समाचार पत्रों की प्रसार संख्या तेजी से बढ़ रही है। अलग-अलग बोलियों में अखबार प्रकाशित हो रहे हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो और टेलीविजन अपने कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस स्मार्टफोन के द्वारा हम सोशल मीडिया के संपर्क में रहते हैं, वहां भी भारतीय भाषाओं का विशेष ख्याल रखा जाता है।

आज से कुछ समय पहले तक गांवों की खबरों के लिए चार चार दिन तक इंतजार करना पड़ता था, जबकि आज व्हाट्सएप और ईमेल के द्वारा आसानी से खबरें प्राप्त हो रही हैं। जिलों, कस्बों और मोहल्लों से आज अखबार प्रकाशित हो रहे हैं। ईमेल से अखबारों के पृष्ठ भेजना आसान हो गया है। पहले अंग्रेजी भाषा के अखबारों पर निर्भरता ज्यादा होती थी, जिसके भारतीय पाठक मात्र 15 प्रतिशत हैं। अब जब अलग-अलग बोलियों और भाषाओं में अखबार प्रकाशित हो रहे हैं, तो सूचना सशक्तिकरण बढ़ रहा है। अब विभिन्न दूतावासों के मीडिया प्रकोष्ठ और विदेशी एजेंसियां भी खबरों के लिए क्षेत्रीय एवं भाषाई मीडिया का लाभ ले रहे हैं। दूसरी तरफ हर अखबार अपने ईपेपर के जरिए दूरदराज के पाठकों तक पहुंच रहा है। हम सब जानते हैं कि इंटरनेट की कोई सीमा नहीं है, ऐसे में क्षेत्रीय अखबार विदेशी धरती पर भी उसी दिन पढ़े जा रहे हैं, जिस दिन वे प्रकाशित होते हैं।

भाषा का संकट

आप वर्ष 2040 की कल्पना कीजिए। तब तक हमारा भारत विश्व की एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका होगा। गरीबी, कुपोषण, पिछड़ापन काफी हद तक मिट चुके होंगे। देश के लगभग 60 प्रतिशत भाग का शहरीकरण हो चुका होगा। सारा देश डिजिटल जीवन पद्धति को अपना चुका होगा। अब आप सोचिए कि उस भारत के अधिकतर नागरिक अपने जीवन के सारे प्रमुख काम किस भाषा में कर रहे होंगे? पूरे देश में शिक्षा, प्रशासन, व्यापार, शोध, पत्रकारिता जैसे हर बड़े क्षेत्र में किस भाषा का उपयोग हो रहा होगा? वह देश भारत होगा या सिर्फ़ इंडिया? उस इंडिया में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हमारी 22 बड़ी और 1600 से अधिक छोटी भाषाओं-बोलियों की स्थिति क्या होगी? वर्तमान में जिस तरह अंग्रेजी का चलन तेजी से बढ़ रहा है, क्या उसके बीच हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं को स्थान मिलेगा।

यूनेस्को के पूर्व महानिदेशक कोचिरो मत्सूरा ने कहा था कि, एक भाषा की मृत्यु उसे बोलने वाले समुदाय की विरासत, परंपराओं और अभिव्यक्तियों का नष्ट हो जाना है। संसार में लगभग 6000 भाषाओं के होने का अनुमान है। भाषा शास्त्रियों की भविष्यवाणी है कि 21वीं सदी के अंत तक इनमें केवल 200 भाषाएं जीवित बचेंगी। इनमें भारत की सैंकड़ों भाषाएं होंगी। यूनेस्को के अनुसार भारत की आदिवासी भाषाओं में से 196 भाषाएं अभी भी गंभीर संकटग्रस्त भाषाएं हैं। संकटग्रस्त भाषाओं की इस वैश्विक सूची में भारत सबसे ऊपर है। यूनेस्को का भाषा एटलस 6000 में से 2500 भाषाओं को संकटग्रस्त बताता है। भारत की अनुमानित 1957 में कम से कम 1416 लिपिहीन मातृभाषाएं हैं। ये सब इस वक्त संकट में हैं। **शेष पृष्ठ 9 पर**

सनातन धर्म पर हमला करने के लिए अचानक से इतने सारे आक्रांता कहां से आ गये हैं?

दीपक कुमार त्यागी

देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ गई हैं, राजनेता मतदाताओं को हर-हाल में अपने पक्ष में करने के लिए बेहद ही व्याकुल हैं। जिसके चलते ही आजकल चंद राजनेता अपने ऊल-जलूल बयानों से देश की एकता-अखंडता, सामाजिक व धार्मिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे बयानवीर राजनेता अपने क्षणिक राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए अब तो सनातन धर्म को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। हालांकि अहंकार में वशीभूत यह चंद लोग भूल रहे हैं कि सनातन धर्म हमारे प्यारे भारत देश की आत्मा है, मूल पहचान है, कम से कम उसे तो अपनी ओछी राजनीति के लिए निशाना ना बनाये, लेकिन वह फिर भी बाज नहीं आते हैं। आज देश में एक बार फिर से कुछ लोगों के द्वारा सनातन धर्म को समाप्त करने की बात सार्वजनिक मंचों से की जाने लगी है। लेकिन यह लोग भूल जाते हैं कि सत्य, अहिंसा परोपकार आदि के मूलमंत्र के आधार पर आदिकाल से कार्य करने वाले सनातन धर्म को मुस्लिम शासकों, अंग्रेजी हुकूमत व ईसाई मिशनरियों ने भी दुनिया से मिटाने के लिए हजारों वर्षों तक तरह-तरह के हथकंडे अपनाए थे, लेकिन फिर भी वह इस सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर पाये और सनातन धर्म की ओजस्वी धर्म ध्वजा को दुनिया में फहराने से रोक नहीं पाए।

वैसे देखा जाए तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ऊल-जलूल बोलना आजकल हमारे देश में एक फैशन बन गया है। जिस तरह से आज हमारे प्यारे देश भारत में कुछ जिम्मेदार लोगों के द्वारा सनातन धर्म के बारे में तरह-तरह की अनर्गल, तथ्यहीन बयानबाजी की जा रही है, क्या इस तरह की ऐसी झूठी या सच्ची बात किसी अन्य धर्म व मजहब के बारे में कहने की इन राजनेता व लोगों के अंदर हिम्मत है। आज अपने वोटबैंक को साधने की खातिर यह चंद राजनेता लोग सनातन धर्म को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं और एक नई झूठी तथ्यहीन परिभाषा गढ़ने के साथ जनता को सनातन धर्म के खिलाफ बरगलाने में लगे हुए हैं।

जबकि सनातन धर्म के बारे में कटु सत्य यह है कि जनता के बीच सत्य, अहिंसा, परोपकार सहिष्णुता जैसे आदि कारणों से सनातन धर्म आदिकाल से ही देश व दुनिया में बड़े पैमाने पर आम जनमानस के बीच स्वीकार्य है। दुनिया में यही एकमात्र धर्म ऐसा है, जिस धर्म में सत्य पर आधारित बात होती है, अगर आत्मा की बात होती है तो परमात्मा की भी बात होती है। वहीं हमारे आराध्य भगवान राम व कृष्ण आदि अगर पुरुष के रूप में हैं, तो वह मां दुर्गा-लक्ष्मी के स्त्री के रूप में भी विराजमान हैं और सम्मान के साथ पूजनीय हैं। वहीं सनातन धर्म में जीव, जंतु व मानव भी हैं, तो धरा पर उपस्थित साक्षात दिव्य अलौकिक प्रकृति भी है। सनातन धर्म में इतनी अधिक सरलता है कि कोई भी व्यक्ति वेद,

शेष पृष्ठ 9 पर

पृष्ठ 8 का शेष

पुराण, मंत्रों आदि को जाने बिना भी पूरे अधिकार के साथ सनातन धर्म का अनुयाई हो सकता है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके अनुयायी ईश्वर को मानने वाले आस्तिक भी हैं और नास्तिक भी। सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि हमारे घरों में स्थापित किए गए मंदिर में भी अलग तरह की देवी-देवताओं की बहुत सारी प्रतिमाएं होती हैं और धर्म में इतनी ज्यादा सरलता है कि एक परिवार के सदस्य भी अलग-अलग देवी-देवताओं के उपासक हो सकते हैं। एक ही पूजा घर में विभिन्न देवी-देवताओं की एक साथ पूजा करके विश्व का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म विविधताओं के बावजूद भी समाज को एकजुट रहने का हर-पल संदेश देता है। जिस धर्म में लोगों के जीवन में अहम स्थान रखने वाली प्रकृति, जल, थल, वायु व अग्नि की भी पूजा की जाती हो। जो धर्म अपने हर अनुयायियों को यह सिखाता हो कि आप जीवन में किसी भी मानव, जीव-जंतु से ऐसा ही व्यवहार करें जैसा कि व्यवहार आप खुद दूसरे से अपने लिए चाहते हैं। जो धर्म सभी धर्मों की जननी माना जाता है आज कुछ नादान लोग उसको समाप्त करने का सपना देखने कार्य रहे हैं। उस महान सनातन धर्म पर लोगों से भेदभाव करने का निराधार बेतुका आरोप लगा रहे हैं।

वैसे भी हमारे देश के इन सभी तथाकथित बयानवीरों को यह समझना चाहिए कि सनातन धर्म का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो, जिन बातों का हम लोगों के जीवन में शाश्वत महत्व हो वही बातें सनातन धर्म में कही गई है। इसलिए ही दुनिया मानती है कि सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म भी सत्य है। वह सत्य जो कि आदिकाल से दुनिया में चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा। देखा जाये तो सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम-नियम आदि का हर एक व्यक्ति के जीवन में शाश्वत महत्व है और यह तथ्य दुनिया के अन्य सभी धर्मों के उदय के पूर्व ही हमारे ऋषि-मुनियों के द्वारा वेदों में प्रतिपादित कर दिये गये थे। फिर भी कुछ लोग ऐसे महान धर्म को समाप्त करने की हसरत अपने दिल में पाल कर बैठे हैं। इन लोगों को समझना होगा कि आदिकाल से ही सनातन धर्म हर एक व्यक्ति को अनुशासित जीवन जीने की कला सिखाने का कार्य करता है, ना कि लोगों के बीच जहर भरने का कार्य करता है। लेकिन अब देश की जनता को भी समझना होगा कि चंद राजनेता वोटबैंक के लिए बार-बार अपनी काठ की हांडी चढ़ाते हैं जिसको अब चढ़ने से रोकना होगा और देश व समाज के हित में कार्य करने वाले लोगों को चुनकर आगे बढ़ाना होगा, तब ही बार-बार जहर उगलने वाले नेताओं की नफ़रत की दुकान बंद होगी और सनातन धर्म के मानव जगत के उद्देश्य पूर्ण होंगे।

पृष्ठ 7 का शेष

यूनेस्को के कहने पर विश्व के श्रेष्ठ भाषाविदों ने किसी भी भाषा की जीवंतता और संकटग्रस्तता नापने के लिए 9 कसौटियां निर्धारित की हैं। इनमें पहली कसौटी है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के बीच उस भाषा का अंतरण। दूसरी कसौटियों में प्रमुख हैं ज्ञान विज्ञान के आधुनिक क्षेत्रों में उस भाषा में काम हो रहा है या नहीं। वह भाषा नई तकनीक और आधुनिक माध्यमों को कितना अपना रही है? उस भाषा के विविध रूपों का दस्तावेजीकरण कितना और किस स्तर का है? उस समाज की महत्वपूर्ण संस्थाओं की उस भाषा के बारे में नीतियां और रुख़ कैसे हैं? इसमें अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कसौटी हैज्उस भाषा समुदाय का अपनी भाषा के प्रति रुख़ क्या है, भाव क्या है? इनमें से किसी भी कसौटी पर किसी भी भारतीय भाषा को तोल लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा कि भविष्य के संकेत संकट की और इशारा करते हैं या विकास की ओर। भारतीय चरित्र, इजराइली चरित्र जैसा नहीं है, जिसने 2000 साल से मृत पड़ी हिब्रू को आज वैज्ञानिक शोध, नवाचार और आधुनिक ज्ञान निर्माण की श्रेष्ठतम वैश्विक भाषाओं में एक बना दिया है। जिसके बल पर 40 लाख की जनसंख्या वाला इजरायल एक दर्जन से ज्यादा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार जीत चुका है। सारे इस्लामी देशों की शत्रुता के बावजूद अपनी पूरी अस्मिता, धमक और शक्ति के साथ अजेय बना विश्व पटल पर विराजमान है।

अंतर-संवाद और अनुवाद

भाषा मनुष्य की श्रेष्ठतम संपदा है। सारी मानवीय सभ्यताएं भाषा के माध्यम से ही विकसित हुई हैं। याद रखिए...आदिम समाज तो हो सकते हैं, लेकिन आदिम भाषाएं नहीं हो सकतीं। शहीद भगत सिंह ने 15 वर्ष की उम्र में ये लिखा था कि, पंजाब में पंजाबी भाषा के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। गांधी जी ने 1938 में ही स्पष्ट कहा था कि, क्षेत्रीय भाषाओं को उन का आधिकारिक स्थान देते हुए शिक्षा का माध्यम हर अवस्था में तुरंत बदला जाना चाहिए। महात्मा गांधी का ये भी मानना था कि अंग्रेज़ी भाषा के मोह से निजात पाना स्वाधीनता के सब से ज़रूरी उद्देश्यों में से एक है। भाषाओं का राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में योगदान होता है। शब्दों को हमने ब्रह्म माना है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी में 'हरिजन' प्रकाशित किया, लेकिन उसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उसे गुजराती और हिंदी में भी स्थापित किया। भारतीय भाषाओं के बीच अंतर-संवाद को हमें अगर समझना है तो गुजराती में 70 पुस्तकों की रचना करने वाले फादर वॉलेस और गुजरात में कई विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना करने वाले सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में पढ़ना चाहिए। उत्तर-दक्षिण भारत की भाषाओं में व्यापक अंतर होने के बावजूद उनमें अंतर-संवाद और अनुवाद होता आया है।

भाषा ही कराती है मेल-मिलाप

भारत एक छोटे यूरोप की तरह है। यहां विविध भाषाएं हैं और भाषा ही मेल-मिलाप कराती हैं। भाषाई विविधता और बहुभाषी समाज आज की आवश्यकता है और समस्त भाषाओं के लोगों ने ही विश्व में अपनी उपलब्धियों के पदचिन्ह छोड़े हैं। आज हम एक बहुभाषी दुनिया में रहते हैं। दुनियाभर में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवास करते हैं। जहां उनकी भाषाएं और संस्कृति, नए क्षेत्र की भाषा और संस्कृति से एकदम अलग होती है। इसलिए उन्हें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है, जो दोनों संस्कृतियों को आपस में एकीकृत कर सके, जिसके लिए उन प्रवासियों को निश्चित तौर पर एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी एक शिक्षित व्यक्ति को कम से कम तीन भाषा का ज्ञान होता है। यहां के लोगों को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का ज्ञान होता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क साधने के लिए अंग्रेजी भाषा को भी ये लोग सीख लेते हैं।

नरेंद्र मोदी ने बढ़ाई दुनिया में भारत की साख और धाक

डॉ. राकेश मिश्र

स्वयंसेवक से प्रधानसेवक तक की यात्रा के सफल सारथी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनायक के रूप में भारत की साख और धाक दुनिया में स्थापित की है। 17 सितंबर को जब देश के अधिकांश हिस्से में निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है, तो इसी दिवस को आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन मनाया जाता है। आज के समय में भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय हस्ती है तो वह हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैश्विक नेताओं के बीच सर्वोच्च स्थान बनाते हुए उन्होंने भारत को भी शिखर तक पहुंचाया है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय राजनीतिक हस्तियों में शामिल नरेंद्र मोदी का नाम उनके व्यक्तित्व, कार्यशैली, दृढ़निश्चय और क्षमता के कारण न सिर्फ भारत में, बल्कि विश्व पटल पर गूंज रहा है। विदेशों में लगभग 3.50 करोड़ भारतीय मूल के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी चिंता किसी ने की तो नरेंद्र मोदी ने की और सभी के लिए भारत सरकार ने एक नीति बनाई, जिससे दूसरे देशों में रहनेवाले भारत के लोगों को एक पहचान मिली। वंदे भारत मिशन के तहत संकटकाल के समय 70 लाख देशवासियों को सुरक्षित भारत लाया गया। हाल ही में चंद्रयान-3 की सफलता से दुनिया दंग हो गई और भारत की ताकत का लोहा माना।

आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए तमाम सर्वेक्षणों में नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर नेता के रूप में शामिल किया गया। हाल ही में हुए मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण में 76 प्रतिशत अनुमोदन रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार पुन: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले कुछ सालों से लगातार सर्वेक्षण में टॉप पर बने हुए हैं।

हाल ही में जी 20 की बैठक का ऐतिहासिक होना इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी का व्यक्तित्व और भारत की गौरवगाथा को पूरी दुनिया ने न केवल स्वीकार किया है, बल्कि उसके प्रति सम्मान भी दिया है

। यूं तो 2014 के बाद एक बड़ा बदलाव सामने आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण वैश्विक स्तर स्तर पर भारत की ताकत काफी बढ़ी है। विदेश में भारत ताकतवर होकर उभरा है। चाहे यूक्रेन युद्ध के समय वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने का मसला हो या कोविड के दौरान दुनिया भर में टीका भेजने की पहल, इन सबमें नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि और भी निखर कर सामने आई है। एक बड़ा बदलाव यह भी आया कि अब तक वैश्विक कार्यक्रम और वैदेशिक नीति आम जनता तक नहीं जाती थी। जब भारत में सबसे बड़ा कूटनीतिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें विश्व के तमाम ताकतवर नेता जुटे। इससे हर भारतवासी न सिर्फ अवगत हुआ, बल्कि गौरवान्वित भी हुआ। जी 20 बैठक के दौरान दुनिया को भारत की धरोहर और संस्कृति से अवगत कराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का नाम और ऊँचा किया। दुनिया के सभी ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों को खादी के गमछों के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए लाना अपने आप में अद्भुत घटना रही ।

जी 20 में भारत की इस कामयाबी के बाद पूरी दुनिया ने मोदी जी की कुशलता का लोहा माना। जहां सम्मेलन से पहले भारत पर दोनों ओर से बहुत दबाव था। इसमें एक ओर अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी देश थे तो दूसरी ओर रूस और चीन। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी पक्ष का अपना आग्रह था और रूस का अपना। लेकिन, मोदी जी इस दबाव के सामने न तो झुके और न ही अपनी नीतियों से समझौता किया, बल्कि अपने हिसाब से चीजें तय कीं। इसमें उन्होंने सफलता भी हासिल की। आज पूरी दुनिया में मोदी को सम्मान से देखा जाता है और उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में स्वीकार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका और अन्य विकासशील देशों की आवाज बनकर आए और अफ्रीकी यूनियन को भी जी-20 में सम्मिलित कराकर विश्व में अपना प्रभाव छोड़ा। ब्राजील के हाथ में अगली बैठक की अध्यक्षता का दायित्व सौंपकर उन्होंने विश्व को 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का संदेश दिया।

प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि जिस ब्रिटेन ने हम पर दो सौ वर्षों तक राज किया, उसे पछाड़कर भारत दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था बनकर अपने सामर्थ्य को दिखाया है। आज स्टील उत्पादन में हम दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं, ऑटोमोबाइल में भारत तीसरे स्थान पर है। आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी रहती है। कोरोना काल में लगातार देशवासियों के साथ-साथ विश्व समुदाय के साथ सामंजस्य बनाने वाले और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में लोकप्रियता में वृद्धि हुई है।

नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व ही उनको दूसरे राजनीतिज्ञों से अलग बनाता है। 26 मई 2014 को सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने अन्य देशों के साथ संबंधों को नया आयाम देने की दिशा

शेष पृष्ठ 11 पर

कुछ लोग जिंदगी में खुद कुछ करने की बजाय दूसरों की कमियां ही निकालते रहे जाते हैं

ललित गर्ग

प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनपथ, कार्यक्षेत्र में सफलता के सपने संजोता है। पर, सबके सब सपने सच में नहीं बदलते। अथक परिश्रम के पश्चात भी यदि सफलता न मिले तो निराश-हताश होना स्वाभाविक है। निराशा का गहरा कुहरा व्यक्ति के मनोबल और विश्वास को कमजोर बना देता है। वह हीनभावना से ग्रस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति से उबरने के लिए जेनकाऊल ने कहा- स्मरण रखो- 'आने वाला दिन आज की अपेक्षा अधिक उल्लासपूर्ण होगा। दिन के बाद रात आती है, तो रात के बाद उजली सुबह भी जरूर आएगी। उसके पूरे-परे उपयोग की तैयारी करो।' इसका अर्थ है- आशा और विश्वास की दीवार को कभी मत दरकने दो। यह आशावादी दृष्टिकोण सफलता का पहला सोपान है। व्यक्तित्व का शक्तिशाली घटक है। निराशा एवं अनिश्चितता के दौर में हम ऐसी सभी चीजों से दूर भागने लगते हैं, जिनसे हमें असुविधा होती है। हम समय ऐसे कामों में बिताने लगते हैं, जो हमारे लिए बेहतर विकल्प नहीं होते। अपनी बेचौनियों को धैर्य से जीते हुए सही दिशा में चलने के बजाय हम आसान रास्तों की ओर दौड़ने लगते हैं। कहते हैं कि डर कर फैसले करने के बजाय सही राह की प्रतीक्षा करना ही सही होता है।

जीवनयात्रा में व्यक्ति अनेक खट्टे-मीठे अनुभवों से गुजरता है। वह कभी फिसलता भी है, गिरता भी है, गलतियां भी करता है, किन्तु हर चूक उसे चेताती है, हर ठोकर ठीक चलने का सबक सिखाती है, हर असफलता सफलता के द्वार खोलती है। इस प्रकार वह प्रत्येक घटना से बोध पाठ पढ़ता है और परिपक्वता के साथ-साथ अनुभव प्रवण भी बनता जाता है। उन अनुभवों से प्रेरणा लेकर जो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, वे अपने व्यक्तित्व की स्वतंत्र पहचान बना लेते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन जाते हैं। लेखक व प्रोफेसर मॉरी शेजवार्ट्ज ने अपनी किताब 'ट्यूसडेज विद मॉरी' में लिखा है, 'अपने आसपास मैं रोज सैकड़ों लोगों को देखता हूं। इनमें से कई हैं, जो सफल हैं, व्यस्त हैं, पर इतने थके हुए दिखते हैं जैसे अधमरे हों। मैं मानता हूं कि वे उस रास्ते पर नहीं चल रहे, जिन पर उन्हें चलना चाहिए।'

सही रास्ता वो है, जो आपको आशावादी बनाए, संतोष दे, आपको मुस्कराने की वजह दे। इन सबके लिए आपको सफल, अमीर या शक्तिशाली बनने की बजाय संवेदनशील एवं करुणाशील बनने की जरूरत है।

संवेदनशीलता का अर्थ है दूसरों की कठिनाइयों को जानने समझने की क्षमता। भौतिक/आर्थिक विकास की दिशा में निरंतर प्रतिस्पर्धात्मक दौड़, औद्योगिक विकास, मोबाइल संस्कृति का बढ़ता प्रभाव, सोशल मीडिया का बढ़ता वर्चस्व- इन सब कारणों से आज का मनुष्य अधिक आत्मकेन्द्रित होता जा रहा है। करुणा और संवेदनशीलता के स्रोत सूख रहे हैं। विश्व की भौगोलिक सीमाएं सिमट रही हैं, दूरिया मिट रही हैं किन्तु मनुष्य-मनुष्य के बीच बिन्ध्याचल खड़े हो रहे हैं। संवादहीनता बढ़ रही है। संवेदनशीलता समाप्त हो रही है। मानव-मानस मरुस्थल बन रहा है। ऐसी स्थिति में भावनात्मक रिश्ते ही संबंधों की धरती पर स्नेह-सौहार्द की हरियाली उगा सकते हैं।

अमेरिकी लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर ब्रिएना विएस्ट भावनात्मक बुद्धि पर अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उनके अनुसार जब निजी स्तर पर हमारा दर्शन सिर्फ यही रह जाए कि हम बिना कोई प्रश्न पूछे वही करने लगें, जो हमें कहा जाए, तो इसका अर्थ है कि हम उपभोक्तावाद या अपने अहं या किसी के प्रति अंध श्रद्धा का शिकार हो रहे हैं या किसी ऐसे की इच्छा का पोषण कर रहे हैं, जो हमें नियंत्रित करना चाहता है। जबकि सफल एवं सार्थक जीवन के लिये हमें स्व-अनुभव एवं प्रयोग की भूमि पर चलना होगा। स्व-अनुभव संपदा का अर्जन और समाज के व्यापक हित में उसका नियोजन करने वाले व्यक्ति सहज ही सर्वत्र सम्मानित एवं सफल मान जाते हैं।

पृष्ठ 10 का शेष

में कार्य करना आरम्भ कर दिया था। अपने पड़ोसियों से संबंध सुधारना मोदी सरकार की विदेश नीति के केन्द्र में रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अथक मेहनत से दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदला है। स्मरणीय हो कि नरेंद्र मोदी ने प्रथम दिन से ही विदेश नीति पर काम करना शुरू कर दिया था। मोदी जी के प्रयास से योग को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है। भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर अग्रणी रहकर कार्य कर रहा है।

अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां तेजी से बदलती रहती है। उसके अनुरूप अपनी नीतियों में फेरबदल करना भी आवश्यक हो जाता है। इसके लिए लचीलेपन एवं कठोर, दोनों ही नीतियों की आवश्यकता होती है। अतीत में भारतीय विदेश नीति में इसका अभाव दिखा, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति व्यावहारिक मोर्चे पर पूरी तरह परिपक्व रही है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति में पड़ोसियों को प्राथमिकता देने का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे इन देशों को लेकर भारत की दृष्टि बदली है। विदेश नीति में आया यह बदलाव उपयुक्त एवं तार्किक है, क्योंकि सदा परिवर्तनशील विदेश नीति को किसी एक लकीर के हिसाब से नहीं चलाया जा सकता है। समय और विषय के हिसाब से निर्णय लेने होते हैं। तभी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति संभव हो सकेगी। मोदीजी के नेतृत्व में भारत सरकार की विदेश नीति इसी व्यवहारिक राह पर चल रही है। मोदीजी के कारण भारत की विदेश नीति सफल रही है और व्यवहारिक रणनीति पर काम हुआ है। भारत सरकार तमाम दबावों को दरकिनार करते हुए व्यावहारिक विदेश नीति की राह पर चल रही है। हर वैश्विक मामलों में अपना नजरिया साफ करने की ताकत सिर्फ भारत को है।

इस समय अमेरिका, रूस, इजरायल, जापान, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया जैसे कई देशों से भारत के मधुर संबंध है। हम सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले तीसरे राष्ट्र बने। आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का विश्वगुरु बनना निश्चित है। आज उनके जन्मदिन पर उनके सुखद, स्वस्थ, सफल एवं यशस्वी जीवन की अनंत मंगलकामनायें संपूर्ण देशवासी कर रहे हैं।

सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी सदस्य देश स्वभाषा का उपयोग करके ही हर क्षेत्र में ताकतवर बने हैं

नीरज कुमार दुबे

आप सभी को हिंदी दिवस पर बहुत बहुत बधाई। हमारी राजभाषा, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी की विकास यात्रा अनवरत जारी रहे और हिंदी सभी भारतीय भाषाओं को साथ लेकर आगे बढ़ती रहे, यह हमारी शुभकामनाएं हैं। वैसे आज जब हम हिंदी दिवस मना रहे हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी की सेवा हमें साल के बाकी दिनों में भी करती रहनी है। जहां तक हिंदी दिवस की बात है तो यह खुशी का अवसर तो है लेकिन यह भी एक सत्य है कि 14 सितंबर को मनाया जाने वाला हिंदी दिवस एक सरकारी औपचारिकता बनकर रह गया है। यदि भारत की विभिन्न सरकारों और जनता को सचमुच स्वभाषा का महत्व पता होता तो हिंदी की वह दुर्दशा नहीं होती, जो आज भारत में है। हमें देखना चाहिए कि आज तक दुनिया का कोई भी देश यदि महाशक्तिशाली और महासंपन्न बना है तो वह स्वभाषा के माध्यम से बना है। सुरक्षा परिषद् के पांचों स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन अपने देश की शिक्षा, चिकित्सा, संसद, सरकार, अदालतों और अपने दैनिक व्यवहार में उच्चतम स्तर तक स्वभाषा का ही प्रयोग करते हैं। स्वभाषा में ही हर कार्य करने का अर्थ यह नहीं है कि विदेशी भाषाओं का प्रयोग और उपयोग करना सर्वथा अनुचित है। विदेशी भाषाओं का उपयोग अनुसंधान, कूटनीति, विदेश-व्यापार आदि के लिए हम करें और जमकर करें, यह जरूरी है लेकिन हम किसी एक विदेशी भाषा को अपना सर्वस्व बना लें और अपनी भाषाओं को उसकी दासी बना दें यह तो ठीक नहीं है।

हिंदी-दिवस पर भारत की जनता और सरकार, दोनों को कुछ ठोस संकल्प लेने चाहिए। भारत के सभी नागरिक यह संकल्प ले सकते हैं कि वे अपने हस्ताक्षर अपनी मातृभाषा या हिंदी में ही करेंगे। वे अंग्रेजी या किसी भी विदेशी भाषा में हस्ताक्षर नहीं करेंगे। देखा जाये तो देश के ज्यादातर पढ़े-लिखे लोग अपने दस्तखत अंग्रेजी में ही करते हैं। इसके अलावा विभिन्न शहरों के बाजारों में लगे नामपट यदि

हिंदी और स्थानीय भाषाओं में लगे हों तो खरीदारों को ज्यादा आसानी होगी। माल ज्यादा बिकेगा। कुछ प्रांतों ने स्थानीय भाषा के इस प्रावधान को कानूनी रूप भी दिया है। सारे देश के बाजारों के लिए इस तरह के नियम क्यों नहीं लागू किए जा सकते हैं ? आम लोगों को चाहिए कि वे अपने परिचय-पत्र भी भारतीय भाषाओं में छपवाएं। अपने निमंत्रण-पत्र भी अपनी स्थानीय भाषा और हिंदी में छपवाए जा सकते हैं। अब से लगभग 50 साल पहले जब स्वभाषा आंदोलन तेजी से चला था तो सैकड़ों लोग ऐसे भी थे, जो अंग्रेजी में निमंत्रणों के कार्यक्रमों का बहिष्कार कर देते थे।

आजकल हमारी बोलचाल में, अखबारों और टीवी चैनलों में अंग्रेजी शब्दों और मुहावरों का प्रयोग भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कई बार तो उस बोले और लिखे हुए का अर्थ निकालना मुश्किल हो जाता है। भाषा अलग भ्रष्ट होती है। संवाद का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों को पचा लेने की क्षमता को खो दें। हिंदी तो अत्यंत समर्थ भाषा बनी ही इसलिए है कि इसने सैंकड़ों देशी और विदेशी भाषाओं और बोलियों के शब्दों को पचा लिया है। उसका शब्द सामर्थ्य और अभिव्यक्ति की क्षमता अंग्रेजी के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। वह संस्कृत की पुत्री और भारतीय भाषाओं की भगिनी है।

हिंदी-दिवस पर भारत की जनता यह संकल्प भी ले कि वह हिंदी को नौकरशाही के शिकंजे से मुक्त करेगी। आज भी देश का शासन हमारे नेता कम और नौकरशाह ज्यादा चलाते हैं। वे आज तक अंग्रेजी काल की गुलाम मानसिकता से मुक्त नहीं हुए हैं। यदि हमारे नेता दृढ़ संकल्पी हों तो भारत में से अंग्रेजी का वर्चस्व वैसे ही चुटकियों में खत्म हो सकता है, जैसे व्लादिमीर लेनिन ने रूस में फ्रांसीसी और तुर्की में अतातुर्क ने अरबी लिपि का किया था। यदि सारे सरकारी काम-काज से अंग्रेजी को हटा दिया जाए तो समस्त भारतीय भाषाएं और हिंदी अपने आप जम जाएगी। बस, सावधानी यही रखनी होगी कि किसी अहिंदीभाषी को कोई असुविधा न हो।

यदि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की तरह एक अनुवाद मंत्रालय भी कायम कर दे तो बहुभाषी भारत में यह एक चमत्कारी काम होगा। भारत के किसी भी नागरिक को स्वभाषा का प्रयोग करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। संसद और विधानसभा के कानून स्वभाषाओं में बनने शुरु हो जाएंगे, अदालतों के फैसले और बहसें जनता की भाषा में होंगी, विश्वविद्यालयों की ऊँची पढ़ाई और शोधकार्य भी भारतीय भाषाओं में होने लगेंगे। सारे स्कूलों और कॉलेजों से अंग्रेजी की अनिवार्य पढ़ाई पर प्रतिबंध होगा। कोई भी विषय अंग्रेजी माध्यम की बजाय भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाया जा सकेगा। विभिन्न विषयों की पुस्तकें और ताजा शोध-लेख, जो विदेशी भाषाओं में होंगे, वे भारतीय छात्रों को उनकी सहज और सरल भाषा में मिलने लगेंगे। विदेशी भाषा को रटने और समझने में जो शक्ति फिजूल खर्च होती है, उसका उपयोग छात्रों की मौलिकता बढ़ाने में होगा। इसके अलावा छात्रों को सिर्फ अंग्रेजी नहीं, कई विदेशी भाषाएं पढ़ने की स्वैच्छिक सुविधा भी दी जाए ताकि हमारे विदेश व्यापार, कूटनीति और शोधकार्य में नई जान आ जाए।

यदि हम भारत की संसद, सरकार, अदालतों, शिक्षा, चिकित्सा और जन-जीवन में हिंदी और स्वभाषाओं को उनका उचित स्थान दिलवा सकें तो फिर उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भी प्रतिष्ठित करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि सरकारी नौकरियों से अंग्रेजी की अनिवार्यता हट जाए तो देश के करोड़ों गरीबों, पिछड़ों, ग्रामीणों को आगे आने के अपूर्व अवसर मिल सकेंगे।

बहरहाल, हर 14 सितंबर को भारत सरकार हिंदी दिवस मनाती है।

अदालतों से मिलने वाली लताड़ की अब ममता सरकार को आदत-सी पड़ गयी है

योगेंद्र योगी

कानून-व्यवस्था से खिलवाड़, भ्रष्टाचार और वोट बैंक के लिए सरेआम तुष्टिकरण जैसी नीतियों के कारण पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जितनी लताड़ खाई है, उतनी देश के किसी अन्य राज्यों की सरकारों ने शायद ही कभी खाई हो। आश्चर्य की बात यह है कि अदालतों से मिली मुकदमों में हार और फटकार के बावजूद ममता सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। ममता सरकार का रवैया संविधान के कायदे-कानूनों का उल्लंघन करना रहा है। विपक्षी दलों ने ममता सरकार की इस प्रवृत्ति पर कभी पुरजोर तरीके से विरोध नहीं किया। सत्ता में होने का बेजा फायदा उठाने की लगातार बढ़ती पुनरावृत्ति पर अदालतों ने अंकुश लगाया है। ममता सरकार का रवैया ऐसा रहा है जैसे पश्चिम बंगाल भारत के संवैधानिक दायरे से अलग कोई देश हो।

नया मामला पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकायों में भर्ती घोटाले से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल सरकार को अन्य मामलों की तरह इसमें भी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकाय मामले में दखल देने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि स्थानीय निकाय भर्ती और शिक्षक भर्ती घोटाले में लिंक है। इन दोनों मामले में वो सीबीआई और ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली तीन जजों की पीठ ने कथित घोटाले में सीबीआई और ईडी जांच को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अर्जी पर राहत देने से इंकार कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदी वाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने इस दलील को मान लिया कि ये सब बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सीबीआई जांच काफी आगे पहुंच गई है। अब इसमें दखल देते हुए रोकना उचित नहीं है। इससे पहले भी ममता सरकार भ्रष्टाचार सहित कई दूसरे महत्वपूर्ण मामलों में सुप्रीम कोर्ट से हार का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट मिली लताड़ और हार के बावजूद ममता सरकार के रवैये में कोई विशेष सुधार नहीं आया। सरकार की ना तो कार्यशैली बदली और न ही तृणमूल कांग्रेस में कोई तब्दीली नजर आई। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की बिना यूपीएससी के दखल के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की अनुमति देने की याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के मामले में कहा था कि हमारे पिछले आदेश में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने बार-बार एक ही तरह की याचिका दाखिल करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के आवेदन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

सुप्रीम कोर्ट एक पुराने आदेश में कह चुका है कि हर राज्य को डीजीपी की नियुक्ति से पहले यूपीएससी से योग्य अधिकारियों की लिस्ट लेनी होगी। उसी लिस्ट में से चयन करना होगा। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना था कि यह व्यवस्था गलत है। राज्य सरकार को चयन का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था को लेकर भाजपा और अन्य विपक्षी दलों की राज्यों सरकारों को कोई आपत्ति नहीं जताई। इन मामलों की तरह ही इस साल पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जांच सौंपने का आदेश दिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने साफ कहा कि हम विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।

दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने एनआईए को जांच ट्रांसफर करने के हाई कोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए कहा था कि किसी भी विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं किया गया था और यह निर्देश राजनीतिक रूप से पारित किया गया था। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की तरफ से याचिका डाली गई थी। 27 अप्रैल को हाई कोर्ट ने रामनवमी समारोह के दौरान और उसके बाद हावड़ा के शिबपुर और हुगली जिलों के रिशरा में हिंसा की घटनाओं की एनआईए से जांच कराने का आदेश दिया था। ममता सरकार को कानून को चुनौती देने के साथ भ्रष्टाचार जैसे मामलों में कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी। ऐसे ही एक मामले में सरकार ने कोर्ट का रुख किया किन्तु शीर्ष अदालत में जाना सरकार के काम नहीं आ सका। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अभिषेक बनर्जी की अपील पर सुनवाई में दिया। जिसमें हाईकोर्ट के ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो को कथित घोटाले में उनसे पूछताछ करने की अनुमति देने को चुनौती दी गई थी।

बसपा अकेले के चक्कर में वोटकटआ पार्टी बनकर न रह जाये

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट का नतीजा भारतीय जनता पार्टी से कहीं अधिक बहुजन समाज पार्टी के लिए खतरे की घंटी नजर आ रहा है। घोसी में वोटिंग से चंद घंटे पहले बसपा सुप्रीमों मायावती ने जिस अलोकतात्रिक तरीके से अपने वोटरों से वोट नहीं देने या फिर नोटा का बटन दबाने का आहवान किया था उसे दलित वोटरों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और समाजवादी पार्टी के पक्ष में खुलकर मतदान किया। यदि ऐसा न होता तो घोसी में समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी जीत कभी नहीं मिलती। समाजवादी पार्टी बसपा के दलित वोट बैंक को अपने में मिलने के लिए काफी समय से हाथ-पैर मार रही थी, उसका यह सपना काफी हद तक घोसी में पूरा हो गया। बसपा सुप्रीमों को यह समझना होगा कि एक बार दलित वोटर ने उनसे किनारा कर लिया तो दोबारा वापसी असंभव नहीं तो मुश्किल जरूरी हो सकती है। वैसे भी दलित वोटर अपने लिये नये सियासी ठिकाने की तलाश कर रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह है मायावती का राजनीति से मोहभंग होना। बसपा सुप्रीमों अब राजनीति में काफी कम समय देती हैं। पार्टी के पुराने नेताओं ने भी बसपा से दूरी बना ली है।

घोसी उपचुनाव के नतीजे ने बसपा के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के अरमानों को भी बड़ा झटका दिया है। अच्छा होता कि बसपा घोसी चुनाव से दूरी नहीं बनाती, इससे बसपा को कम से कम अपने वोट बैंक में बिखराव तो नहीं देखने को मिलता। मायावती का चुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर इस लिए भी उंगली उठ रही है क्योंकि कुछ समय पूर्व आजमगढ़ लोकसभा उप-चुनाव में बसपा ने शानदार प्रदर्शन किया था, भले वह चुनाव नहीं जीत पाई थी ,लेकिन दलितों के साथ-साथ मुस्लिम वोटरों ने भी उसके पक्ष में बड़ी तादात में मतदान किया था, जिसके चलते सपा तीसरे नंबर पर सिमट गई थी। अच्छा होता मायावती आजमगढ़ से निकले ट्रेंड को घोसी में भी अपना प्रत्याशी उतार कर पार्टी के लिए दलित-मुस्लिम वोट बैंक की संभावनाएं बरकरार रखती, लेकिन बसपा की गैरमौजूदगी में हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित सपा की जीत से अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में

पिछड़ो-दलितों और अल्पसंख्यकों (पीडीए) का समाजवादी पार्टी या आइएनडीआइए की तरफ झुकाव बढ़ने के प्रबल आसार हैं।

राजनीति के जानकार कहते हैं बसपा सुप्रीमों यदि अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करती हैं तो यह उनके लिए आत्मघाती साबित होगा। एनडीए और आइएनडीआइए की सीधी लड़ाई में अकेले चुनाव मैदान में उतरने वाली बसपा को अबकी लोकसभा चुनाव में खाता खोलने तक की चुनौती से जूझना पड़ सकता है। राजनैतिक पंडित समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में 21.12 प्रतिशत वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद बसपा घोसी उपचुनाव के मैदान से दूर क्यों रही। यह सच है कि वैसे तो बसपा अमूमन उपचुनाव से दूर रहती है, परंतु घोसी उपचुनाव के बारे में कहा जा रहा है कि बसपा प्रमुख मायावती ने सोची-समझी रणनीति के तहत दूरी बनाए रखी. चूंकि माना जाता रहा है कि ज्यादातर उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी की ही जीत होती है और भाजपा ने घोसी सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए निषाद पार्टी, अपना दल के साथ ही एनडीए में सुभासपा को भी ले लिया इसलिए उसकी ही जीत की संभावना ज्यादा नजर आ रही थीं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और निकली।

दरअसल, मायावती को करीब से जानने वालों को लगता है कि घोसी में भाजपा के जीतने की दशा में मायावती अल्पसंख्यकों को फिर यही समझाने की कोशिश करती कि भाजपा का मुकाबला सपा-कांग्रेस का आइएनडीआइए गठबंधन नहीं कर सकता। बसपा ही लोकसभा चुनाव में अकेले भाजपा को हरा सकती है, इसीलिए उपचुनाव के दरमियान भी मायावती बार-बार यही कहती रहीं कि वह न एनडीए और न ही आइएनडीआइए गठबंधन के साथ हैं। निश्चित तौर पर आइएनडीआइए में शामिल कांग्रेस, रालोद के समर्थन के साथ सपा प्रत्याशी की जीत से मायावती के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की रणनीति को तगड़ा झटका लगा है। माना जा रहा है कि सपा की जीत से लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों का आइएनडीआइए की तरफ झुकाव बढ़ेगा। ऐसे में एनडीए और आइनडीआइए प्रत्याशियों के बीच सीधी लड़ाई होगी।

बसपा अकेले चुनाव मैदान में कूदेगी तो यह तय माना जायेगा कि इससे भाजपा को ही ज्यादा फायदा होगा। गौरतलब हो, सपा से गठबंधन कर लोकसभा चुनाव 2019 में 10 सीटें जीतने वाली बसपा वर्ष 2014 में अकेले चुनाव लड़ने पर शून्य पर सिमट कर रह गई थी। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में बसपा को दलितों या अल्पसंख्यकों आदि का जो भी वोट हासिल होगा उसका नुकसान आइएनडीआइए को होगा और सीधा लाभ भाजपा को ही मिलेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में मायावती ने प्रत्याशी उतारा तो बसपा तो नहीं जीती लेकिन बसपा के लड़ने से सपा चुनाव हारी और फायदे में भाजपा रही थी। इसी तरह यदि घोसी सीट के उपचुनाव के मैदान में बसपा उतरती तो परिणाम पलट भी सकते थे।

ऋषि सुनक का भारत में दामाद जैसा स्वागत भारतीय संस्कृति और परम्पराओं की श्रेष्ठता को दर्शाता है

नीरज कुमार दुबे

ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के लगभग साल भर बाद भारत के पहले दौरे पर पहुँचे ऋषि सुनक के स्वागत के लिए खासतौर पर भारत में उत्साह दिखा। एक तो ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं दूसरा उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भारत के मशहूर उद्योगपति नारायण मूर्ति की बेटी हैं, तीसरा ऋषि सुनक अपने हिंदुत्व पर गर्व करते हैं और सनातन धर्म में गहरी आस्था रखते हैं और चौथा उनके दिल में भारत के लिए विशेष स्थान भी है। पिछले साल दीवाली पर जब ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की कमान संभाली थी तब उनका देश अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर लगातार परेशानियां झेल रहा था लेकिन ऋषि सुनक ने अपने सूझबूझ वाले नेतृत्व के चलते हालात को जल्द ही संभाल लिया। इसके अलावा चाहे रूस-यूक्रेन का मुद्दा हो या अन्य कोई वैश्विक चुनौती, सभी पर ऋषि सुनक आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए मुद्दों का हल तलाशते हुए दिखाई देते हैं। शुक्रवार को जब वह अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ दिल्ली पहुँचे तो हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस और वरिष्ठ राजनयिकों ने स्वागत किया। हवाई अड्डे पर जय सियाराम कह कर उनका स्वागत किया गया जिसके जवाब में उन्होंने भी जय सियाराम कहा।

हम आपको बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में एक साक्षात्कार में ब्रिटेन के भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा था कि ब्रिटेन और भारत के बीच संबंध दोनों देशों के भविष्य को परिभाषित करेंगे। इसके साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 'भारत का दामाद' बताए जाने के संदर्भ का हवाला देते हुए मजाकिया लहजे में कहा कि जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए नयी दिल्ली का उनका दौरा ''बहुत खास'' है। हम आपको याद दिला दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति सुनक की शादी अक्षता मूर्ति से हुई है। नयी दिल्ली की अपनी उड़ान में पत्रकारों से बातचीत में ऋषि सुनक (43) ने कहा कि वह भारत आने को लेकर उत्साहित हैं ''एक ऐसा देश जो मेरे लिए बहुत करीब और प्रिय है।'' इस यात्रा में सुनक के साथ उनकी पत्नी और इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी भी शामिल हैं। सुनक का शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम है।

सुनक ने तीन दिवसीय दौरे के लिए रवाना होने से पहले 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, ''मैं स्पष्ट फोकस के साथ जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहा हूं। वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है। अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाना है। सबसे कमजोर लोगों का समर्थन करना है।'' सुनक ने अपने साथ यात्रा कर रहे संवाददाताओं से कहा, ''यह बहुत खास है। मैंने कहीं देखा कि मुझे भारत के दामाद के रूप में संदर्भित किया गया था, मुझे उम्मीद है कि यह प्यार से कहा गया होगा।'' हम आपको बता दें कि शिखर वार्ता के दौरान ब्रिटेन के एजेंडे में रूस-यूक्रेन संघर्ष को एक प्रमुख विषय के रूप में चिह्नित किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय 'डाउनिंग स्ट्रीट' ने कहा कि भारत की भूमिका और प्रभाव ''महत्वपूर्ण'' है।

सुनक ने संवाददाताओं से कहा, ''एक बार फिर, व्लादिमीर पुतिन जी20 में अपना चेहरा दिखाने में विफल हो रहे हैं। वह अपने खुद के राजनयिक निर्वासन के वास्तुकार हैं, अपने राष्ट्रपति महल में अलग-थलग रहे हैं और आलोचना और हकीकत को रोक रहे हैं। इस बीच, जी20 के बाकी सदस्य यह प्रदर्शित कर रहे हैं हम आगे आएंगे और पुतिन की हार के लिए मिलकर काम करेंगे।''

इस बीच, 'डाउनिंग स्ट्रीट' के प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन यूक्रेन को लेकर अपना समर्थन दिखाने के लिए ''हर अवसर'' का उपयोग करेगा और साथ ही वैश्विक समर्थन को भी बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने कहा, ''मानवाधिकारों और वास्तव में लोकतंत्र पर रूस के हमले को रोकने में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम पुतिन के क्रूर आक्रमण को समाप्त करने के लिए उस प्रभाव का उपयोग करने को लेकर उन्हें प्रोत्साहित करने के वास्ते मोदी या अन्य नेताओं के साथ बैठकें करेंगे।''

हम आपको बता दें कि मोदी-सुनक द्विपक्षीय चर्चा के दौरान भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वार्ता पर भी चर्चा होने की संभावना है। अभी 12 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है लेकिन इसके निष्कर्ष के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है। 'डाउनिंग स्ट्रीट' ने संकेत दिया है कि समझौते के तहत ब्रिटेन की आव्रजन नीति में कोई बदलाव नहीं होगा, हालांकि व्यापार वार्ता के हिस्से के रूप में अल्पकालिक व्यापार वीजा पर चर्चा की जाएगी। हम आपको याद दिला दें कि मोदी और सुनक की आखिरी मुलाकात मई में जापान के हिरोशिमा में जी7 शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई थी।

सनातन और हिंदू संस्कृति का विरोधी साबित हो रहा है विपक्ष का गठबंधन

मृत्युंजय दीक्षित

रामेश्वरम तीर्थ क्षेत्र की धरती तमिलनाडु, एक ऐसा राज्य जो अनेक भव्य एवं दिव्य मंदिरों के माध्यम से सनातन हिंदू संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है वहां के एक राजनैतिक दल ने सनातन धर्म के प्रति निंदनीय, घृणा से भरा और भड़काऊ वक्तव्य देकर भारत की राजनीति को आक्रोष और आक्रामकता से भर दिया है, पूरे देश से तमिलनाडु की द्रमुक सरकार को भंग करने की मांग तक सामने आ रही है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य के युवा कल्याण और खेल मामलों के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन हिन्दू धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया आदि से करते हुए कहा कि सनातन धर्म का विरोध नहीं अपितु इसका पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए। बयान का समर्थन करते हुए कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता है या यह सुनिश्चित नहीं करता है कि आपके पास मानव होने की गरिमा है वह धर्म नहीं है। आरजेडी नेता मनोज झा ने भी उदयनिधि के बयान का शर्मनाक तरीके से स्वागत किया है।

उदयनिधि ने जिस प्रकार हिंदू सनातन समाज के उन्मूलन की बात कही है उससे यह साफ हो गया है कि मोदी व भाजपा को हराने के लिए बना आई.एन.डी.आई.ए. गठबंधन पूरी तरह से सनातन विरोधी गठबंधन बनकर उभर रहा है। जहाँ जहाँ इस गठबंधन में शामिल दलों या उनके नेतृत्व वाली सरकार हैं वहाँ वहाँ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जो सनातन विरोधी हैं। आई.एन.डी.आई.ए. गठबंधन के उत्तर प्रदेश में साथी समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य व समाजवादी पार्टी के लोग हिंदू धर्म संस्कृति का लगातार अपमान कर रहे हैं। बिहार में राजद कोटे के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताकर मुस्लिम तुष्टिकरण किया था और अभी आई.एन.डी.आई.ए. गठबंधन की बैठक में जाने से पहले बिहार की नीतीश सरकार ने दीपावली व रक्षाबंधन सहित कई हिंदू पर्वों के अवकाश को ही समाप्त कर दिया और वह भी तब जबकि बिहार में कई स्कूलों में शुक्रवार के दिन स्कूलों में अवकाश रहता है।

कांग्रेस के नेता पहले ही कई अवसरों पर अपना सनातन हिन्दू संस्कृति विरोधी चरित्र उजागर कर चुके हैं। चुनावों के समय कोट के ऊपर जनेऊ धारण करने वाले दत्तात्रेय गोत्रीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी सनातन हिन्दू समाज का उपहास करने के लिए हिंदू बनकर मंदिर जाने का दिखावा करते हैं और फिर बयान देते हैं कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। आई.एन.डी.आई.ए. गठबंधन में द्रमुक कांग्रेस का एक बड़ा सहयोगी है। जब कांग्रेस पार्टी दिखावे के लिए उदयनिधि के बयान से अपने को अलग करती है तब बहुत ही षड्यंत्रकारी नजर आती है क्योंकि यह वही पार्टी है जो भगवान राम व रामसेतु को काल्पनिक बताती है। इसके नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर मुस्लिम लीग जिसने भारत विभाजन के समय हिंदुओं के साथ खून की

शेष पृष्ठ 17 पर

पृष्ठ 16 का शेष

होली खेलकर सबसे बड़े नरसंहार को अंजाम दिया था और आजादी के बाद उप्र के मुरादाबाद सहित कई दंगों में कराए थे उसको सबसे बड़े सेक्युलर दल का तमगा देते हैं। आजादी के बाद से अब तक सनातन हिन्दू संस्कृति का अपमान व तिरस्कार सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी की ओर से ही किया गया है अत: उसका उदयनिधि के बयान की निंदा करना मात्र एक दिखावा है। वास्तव में उदयनिधि जैसे लोगों को कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है।

आई.एन.डी.आई.ए.गठबंधन में शामिल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी घोर सनातन हिंदू विरोधी हैं। अभी जब मुंबई में इस गठबंधन की बैठक चल रही थी तो उन्होंने अतिथि सम्मान में लगाया जा रहा टीका लगवाने से साफ मनाकर दिया था। बंगाल में आए दिन हिंदुओं के साथ हिंसा की घटनाएँ हो रही हैं। जब ममता बनर्जी दोबारा मुख्यमंत्री बनी थीं तब चुनाव परिणाम आने के बाद से ही सनातन हिंदू समाज को व्यापक हिंसा का सामना करना पड़ा था। एक बड़ी बात है कि ममता बनर्जी की पार्टी की ओर से उदयनिधि की सांकेतिक निंदा भी नहीं की गयी जबकि वो कांग्रेस के कथित मोहब्बत के मॉल में अपनी एक दुकान खोलकर भारत की प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं।

तमिलनाडु के खेल राज्य मंत्री उदयनिधि ने जो नफरती बयान दिया है वह एक बहुत ही सोची समझी साजिश और तुष्टीकरण रणनीति का ही एक भाग है। उदयनिधि के बयान के कई कारण हो सकते हैं क्योंकि वर्तमान में अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का प्रकरण भी सनातन हिंदू समाज के पक्ष में ही जाने वाला है। संपूर्ण विश्व में भारत व भारतीय संस्कृति का डंका बज रहा है। विश्व के 8 देशों में भारतीय मूल के शासनाध्यक्ष बन चुके हैं। अमेरिका में दीपावली पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हुई है। अमेरिका के जॉर्जिया में अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है।

जब से भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आयी है तब से मुस्लिम राष्ट्रों में भी सनातन हिन्दू समाज के मंदिरों का निर्माण होने लगा है जिसके कारण इन सनातन विरोधी मानसिकता वाले लोगों ने महागठबंधन बनाकर सनातन हिन्दू समाज को अपमानित करने का अभियान प्रारम्भ कर दिया है और चुनावों तक यह अनवरत जारी रहने वाला है। तमिलनाडु के खेल राज्य मंत्री स्टालिन का यह बयान राज्य की सनातन हिन्दू विरोधी राजनैतिक कारकों का भी परिणाम है। तमिलनाडु की दो ध्रुवीय राजनीति सदा से ही ब्राह्मण व सनातन विरोधी रही है। द्रमुक का उदय कांग्रेस पार्टी के गर्भ से ही से ही हुआ है। पिछले वर्षों में राज्य में भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ प्रभाव दिखने लगा है।

2019 के बाद से भाजपा नेतृत्व तमिलनाडु को लेकर काफी सक्रिय हुआ है और अन्नामलाई जैसे तेज तर्रार युवा को अध्यक्ष बनाया गया है। अन्नामलाई के जुझारू नेतृत्व के कारण हाल ही में वहाँ भाजपा ने एक देश एक लोग पदयात्रा प्रारम्भ की है जो राज्य की सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। भाजपा की यह पदयात्रा रामेश्वरम से प्रारम्भ की गयी जिसका शुभारम्भ गृहमंत्री अमित शाह ने किया था। राज्य से प्राप्त समाचारों के अनुसार भाजपा की इस यात्रा को तमिलनाडु की जनता में काफी समर्थन मिल रहा है। राज्य की भाजपा इकाई द्रमुक सरकार के काले कारनामों को लगातार द्रमुक फाइल के नाम से उजागर कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं तमिलनाडु में रुचि ले रहे हैं। मोदी जी ने हाल की विदेश यात्राओं में तमिलनाडु का उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर तमिल संस्कृति की विशेषताओं का बखान किया है और तमिल भाषा को सबसे प्राचीन भाषा बताते हुए उसकी महानता का वर्णन करते रहे है। संसद के नये भवन में तमिल संस्कृति का प्रतीक सैंगोल स्थापित किया गया है। उस समय कई तमिल संतों का सम्मान किया गया था। काशी में काशी तमिल संगमम का सफल आयोजन किया गया।

तमिलनाडु की द्रमुक सरकार भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों से घिरी हुई है और उसके मंत्री जेल जा चुके हैं तथा मुख्यमंत्री के परिवार सहित कई और मंत्री व नेता जांच एजेंसियों के रडार में आ गये हैं। द्रमुक सरकार और राज्यपाल के बीच गम्भीर टकराव चल रहा है और राज्यपाल महोदय ने द्रमुक सरकार के कई विधेयकों को कड़ाई के साथ रोक दिया है। राज्य में भाजपा की बढ़ती हुई राजनीतिक उपस्थिति व गतिविधियों को देखते हुए भी द्रमुक सरकार एक बार फिर अपने पुराने पैटर्न पार वापस आ गयी है और वह है हिंदू विरोध।

सनातन हिंदू समाज का उन्मूलन करने का अभियान तो अनादिकाल से ही चला आ रहा है। पता नहीं कितने लोग आये और कितने लोग चले गये, मिट गए किंतु सनातन हिंदू समाज अनंत है और अनंत ही रहेगा। आक्रमणकारी सिकंदर से लेकर मुगल काल व फिर अंग्रेजों के शासन में अनेकानेक बार सनातन हिंदू समाज के उन्मूलन का कुचक्र रचा गया किंतु फिर भी सनातन समाज व उसकी विचारधारा जीवित है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 17 बार मुगल आक्रमण हुआ किंतु वह आज भी विश्व में अपनी विजय पताका फहरा रहा है। अयोध्या को समाप्त करने के न जाने कितने प्रयास हुए किंतु आज अयोध्या में एक बार फिर श्रीरामलला अपनी जन्मभूमि पर विराजने जा रहे हैं। सनातन हिंदू समाज अटल, अजर, अमर और शाश्वत है। इसका उन्मूलन विश्व की कोई भी शक्ति कभी भी नहीं कर सकती। यह बात उदयनिधि मारन, पी. चिदंबरम व उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम, स्वामी प्रसाद मौर्य, मल्लिकार्जुन खड़गे व् उनके पुत्र प्रियांक खड़गे जैसे नेताओं को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए।

स्मरण रहे कि द्रमुक वही पार्टी है जिसके नेता रामास्वामी नायककर ने एक ऐसी झांकी निकाली थी जिसमें भगवान राम, सीता जैसे देवी देवताओ की मूर्तियों की झाड़ू और जूतों से पिटाई की जा रही थी। ये लोग प्राय: हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वाली प्रदर्शनियां भी लगाते रहे हैं। हिंदुओं के पवित्र तीर्थस्थल रामेश्वरम धाम में भी सनातन हिंदू समाज घोर संकट में आ गया है क्योंकि धर्मान्तरण के कारण उनकी संख्या बहुत कम हो गयी है। उदयनिधि का बयान जहरीला व नफरत भरा बयान है जिसमें सनातन हिंदू समाज के उन्मूलन की बात कही गयी है। यह बयान आगामी चुनावों में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। उदयनिधि व उनके समर्थकों को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हिंदू समाज का उन्मूलन करने की बात सोचने वाले लोग कहाँ आए कहाँ चले गए उनका पता नहीं चल रहा है किंतु सनातन सदा रहेगा।

व्यावसायिक वाहनों की बिक्री में तेजी देश में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि को दर्शा रही है

प्रह्लाद सबनानी

भारत में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विकास से सम्बंधित हाल ही में जारी किया गए आंकड़ों का विश्लेषण करने पर ध्यान में आता है कि भारत, दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी हुई है। अप्रैल-जून 2023 तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि चीन में 6.3 प्रतिशत, इंडोनेशिया में 5.2 प्रतिशत, रूस में 4.9 प्रतिशत, अमेरिका में 2.1 प्रतिशत, जापान में 2 प्रतिशत, दक्षिणी कोरिया में 0.9 प्रतिशत, ब्रिटेन में 0.4 प्रतिशत एवं जर्मनी में 0.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

भारत के सेवा क्षेत्र में लगातार मजबूत वृद्धि दर बनी हुई है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अपनी भागीदारी को 60 प्रतिशत से ऊपर बनाए हुए है। अप्रैल-जून 2023 तिमाही में भी सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 10.3 प्रतिशत की रही है। इसमें वित्तीय क्षेत्र, रियल एस्टेट एवं प्रोफेशनल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि दर भी शामिल है। इसी प्रकार व्यापार, होटेल, यातायात, कम्यूनिकेशन एवं ब्रॉडकास्टिंग से सम्बंधित सेवाओं में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत की रही है। कन्स्ट्रक्शन क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम तिमाही में 16 प्रतिशत वृद्धि दर रही थी जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में घटकर 7.9 प्रतिशत की रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में भारत में सबसे तेज गति से वृद्धि दर्ज करने वाले क्षेत्र हैं- वित्तीय सेवाएं एवं रियल इस्टेट 12.2 प्रतिशत, व्यापार, होटेल एवं यातायात 9.2 प्रतिशत, पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन एवं डिफेन्स 7.9 प्रतिशत, कंस्ट्रक्शन 7.9 प्रतिशत, माइनिंग 5.8 प्रतिशत एवं मैन्युफेक्करिंग 4.7 प्रतिशत। विनिर्माण के क्षेत्र में वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए अभी और कदम उठाए जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

भारत से उत्पादों के निर्यात में लगातार 6ठे माह कमी दृष्टिगोचर हुई है। जुलाई 2023 माह में भी उत्पादों के निर्यात में 15.9 प्रतिशत की कमी देखी गई है। भारत से निर्यात किये जा रहे 30 मुख्य उत्पादों में से 19 उत्पादों के निर्यात में कमी दर्ज की गई है। अप्रैल-जून 2023 तिमाही में भी विभिन्न उत्पादों में निर्यात कम ही रहे हैं। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में उत्पन्न हो रही समस्याओं के चलते भारत से उत्पादों में निर्यात कम हो रहे हैं। जब तक इन देशों की आर्थिक स्थिति सुधरती नहीं है तब तक भारत से इन उत्पादों के निर्यात में भी सुधार की सम्भावना कम ही है।

दूसरे, भारत में अगस्त 2023 माह में मानसून की गतिविधियां बहुत कमजोर रही हैं। अगस्त 2023 माह में मानसून की वर्षा लम्बे समय के औसत की तुलना में 35 प्रतिशत कम रही है जो लगभग पिछली एक शताब्दी में अगस्त माह में सबसे कम मानसून की वर्षा है। कुल मिलाकर देश में मानसून की वर्षा सामान्य से 3 से 18 प्रतिशत तक कम रह सकती है। मानसून की वर्षा कम होने का सीधा असर देश के कृषि क्षेत्र पर पड़ेगा। खरीफ की फसल तो कुछ हद तक प्रभावित हुई है। देश में कम वर्षा के कारण पानी के भंडारण पर भी विपरीत असर दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले समय में देश के कुछ भागों में पानी की कमी महसूस की जा सकती है, जिसके चलते रबी की फसल पर भी कुछ विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। परंतु, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सम्पन्न किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत के जिन क्षेत्रों में अनाज का उत्पादन होता है, उन क्षेत्रों में मानसून का मौसम समाप्त होने के पूर्व तक शायद मानसून की वर्षा की अधिक कमी नहीं रहे। अत: वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि क्षेत्र में उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक कम होगा, ऐसा जरूरी भी नहीं है।

केंद्र सरकार एवं कुछ राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत खर्चों में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही कई कम्पनियों की लाभप्रदता में सुधार के चलते इन कम्पनियों ने भी अपने पूंजीगत खर्चों में वृद्धि की है। इस प्रकार, सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कई कम्पनियां अब पूंजीगत खर्च के साइकल में प्रवेश कर गई हैं, इससे आगे आने वाले समय में देश के आर्थिक विकास को गति मिल सकती है। कोरोना महामारी के चलते पर्यटन का क्षेत्र बहुत अधिक प्रभावित हुआ था परंतु इस वर्ष पर्यटन के क्षेत्र में जबरदस्त उछाल देखने में आया है। इससे पर्यटन से सम्बंधित क्षेत्रों जैसे होटेल, यातायात, खुदरा व्यापार आदि में अतुलनीय गतिविधियां दृष्टिगोचर हुई हैं। इन गतिविधियों के आने वाले समय में और अधिक गति पकड़ने का अनुमान है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून 2023) के बाद से भी भारत के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विकास की गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। इससे आभास होता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की शेष अवधि में भी देश में विकास दर ऊंचे स्तर पर बनी रह सकेगी।

आरक्षण देने भर से महिलाओं की स्थिति नहीं सुधर जायेगी, लोगों को अपनी सोच भी बदलनी होगी

ललित गर्ग

भारतीय संसद के नए भवन के पहले सत्र का श्रीगणेश अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक, यादगार एवं अविस्मरणीय रहा। मंगलवार के शुभ दिन अनेक नये अध्याय एवं अमिट आलेख रचे गये, जिनमें सरकार और विपक्ष के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध की दुर्लभ तस्वीर सामने आयी, वहीं 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023' के रूप में नारी शक्ति के अभ्युदय का नया इतिहास रचा गया। यह सुनकर एवं देखकर अच्छा लगा कि सभी नेताओं ने पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर बाबा साहेब अंबडेकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबू राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सभी महान नेताओं को याद किया, जिन्होंने नया एवं सशक्त भारत बनाने में योगदान दिया।

हर राजनीतिक दल महिला उत्थान, उन्नयन एवं विधायी संस्थानों में संतुलित महिला प्रतिनिधित्व के लंबे-चौड़े दावे करते रहे हैं और वादे भी, लेकिन जब समय आता है तो महिलाओं को उनका हक देने में अनेक किन्तु-परन्तु एवं कोताही होती रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में कुल 82 महिला सांसद चुनकर आई थी। जिस देश में आधी आबादी महिलाओं की हो, वहां सिर्फ 15 फीसदी महिलाएं ही लोकसभा पहुंचे तो आश्चर्य ही नहीं, बल्कि विडम्बनापूर्ण ही है। आश्चर्य की बात यह कि 2019 से पहले हुए चुनावों में जीतने वाली महिला सांसदों की संख्या 82 से भी कम रहती आई है। विधानसभाओं के हाल भी कमोबेश लोकसभा जैसे ही हैं। ऐसे हालात में भाजपा एवं मोदी सरकार ने साहस का परिचय देते हुए महिला आरक्षण विधेयक को पेश कर सराहनीय उपक्रम किया है, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। इससे शासन चलाने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो उनके खिलाफ होने वाले अत्याचार के मामले भी कम होंगे। सवाल सिर्फ सांसद-विधायक का ही नहीं है, प्रयास होने चाहिए कि मंत्री पद पर भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े।

महिला आरक्षण को लेकर कई बहसें और विवाद होते रहे हैं। संसद में कई प्रयास किये गये। 1996 में इससे जुड़ा पहला बिल पेश किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण विधेयक लाया गया लेकिन इसके लिए संख्या नहीं जुटाई जा सकी और सपना अधूरा रह गया। महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करने, उनकी शक्ति का उपयोग करने और ऐसे अनेक महान कार्यों के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो पहल की है, इसके लिये वे अभिनन्दनीय है। भले ही विधेयक पारित होने के बावजूद इसका लाभ लेने के लिए महिलाओं को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। यानी 1996 में पहली बार पेश आरक्षण विधेयक के व्यावहारिक रूप में लागू होने में अभी तीन चार साल और लगने के आसार हैं। लेकिन, यहां एक सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर महिला आरक्षण विधेयक संसद में लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बिना आरक्षण के राजनीतिक दल महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पर्याप्त टिकट नहीं दे सकते? मुद्दे की जड़ यह है कि राजनीतिक दल चाहे वह भाजपा हो या कांग्रेस या कोई अन्य दल, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अधिक संख्या में महिला उम्मीदवारों को टिकट देने की शुरुआत आने वाले चुनावों में ही करें, इसके लिए उन्हें किसी कानून की जरूरत नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक दल 'आधी आबादी' को उनका पूरा हक दें, ताकि सामाजिक समरसता का ताना-बाना और मजबूत हो सके।

महिलाओं के युग बनते बिगड़ते रहे हैं। कभी उनको विकास की खुली दिशाओं में पूरे वेग के साथ बढ़ने के अवसर मिले हैं तो कभी उनके एक-एक कदम को संदेह के नागों ने रोका है। कभी उन्हें पूरी सामाजिक प्रतिष्ठा मिली है तो कभी वे समाज के हाशिये पर खड़ी होकर स्त्री होने की विवशता को भोगती रही है। कभी वे परिवार के केंद्र में रहकर समग्र परिवार का संचालन करती हैं तो कभी अपने ही परिवार में उपेक्षित और प्रताड़ित होकर निष्क्रिय बन जाती है। राजनीतिक मंचों पर तो महिलाओं के साथ भेदभाव समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इन विसंगतियों में संगति बिठाने के लिए महिला आरक्षण विधेयक एक सार्थक प्रयास है, अब महिलाओं को एक निश्चित लक्ष्य की दिशा में प्रस्थान करना होगा। राजनीतिक सत्ता एक जरिया बना रहा है, जिसके बल पर सत्ता भी मर्दों के हाथ में केंद्रित करके महिलाओं पर दबदबा कायम रखा जाता रहा है। एक पूर्वाग्रह भी रहा है कि महिलाओं के हाथों में राजनीति सौंप दी गई, तो पुरुषों की सत्ता पलट जाएगी। अभी तक जो महिलाएं संसद पहुंचती रही हैं, उनमें से ज्यादातर अभिजात वर्ग से आती हैं, पर महिला आरक्षण लागू होने से अब दबी-कुचली महिलाएं ज्यादा बड़ी संख्या में ऊपर आएंगी।

महिलाओं को उचित एवं सम्मानजनक स्थान देने में आरक्षण एकमात्र इलाज नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्कों में वर्षों से विधायी संस्थाओं में स्त्रियों की सीटें आरक्षित रही हैं, पर वहां उनके हालात कैसे हैं, यह बताने की जरूरत नहीं। खुद हमारे देश में ही पंचायती राज संस्थाओं में कई सूबों में 50 प्रतिशत तक महिला आरक्षण लागू है।

आगामी लोकसभा चुनावों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है मोहन भागवत का उत्तर प्रदेश दौरा

अजय कुमार

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गया है। आरएसएस की कार्यशैली से कोई अनभिज्ञ नहीं है। आरएसएस अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सीधे तौर पर तो राजनीति में नहीं उतरता है, लेकिन उस नेता और पार्टी का समर्थन करने में उसे जरा भी गुरेज नहीं होता है जो उसकी विचारधारा को मानते हैं और उसे आगे ले जाने के संघ के प्रयास का हिस्सा बनते हैं। प्रत्येक चुनाव से पूर्व आरएसएस की सक्रियता बढ़ जाती है, यह स्वाभाविक तौर पर देखा गया है, लेकिन पहले और आज में विशेष अंतर यह नजर आ रहा है कि अबकी से संघ पर्दे के पीछे से नहीं खुलेआम इस बात की घोषणा कर रहा है कि संघ ने लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका तय कर ली है। लोकसभा चुनावों से पहले संघ गांव-गांव अपनी पहुंच बढ़ाने में जुट गया है। जब पूरा देश श्री गणेश उत्सव मना रहा होगा तब संघ प्रमुख मोहन भागवत 22 से 24 सितंबर तक लखनऊ में डेरा डाले होंगे। इससे पहले 19-20 सितंबर को भाजपा और संघ के बीच समन्वय बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। इस बैठक में सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सह सरकार्यवाह अरुण कुमार की उपस्थित रहेंगे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत का चुनाव से पहले होने वाला दौरा अहम है। इससे पहले सर कार्यवाह और सह सरकार्यवाह भी आएंगे। दरअसल, संघ की योजना 2024 के चुनाव से पहले सियासी नब्ज भांपने के साथ अगली तैयारी में जुट जाने की है। दरअसल, भले ही सीधे तौर पर राजनीतिक बातें नहीं करता है, लेकिन संघ के कोर एजेंडे भाजपा के लिए सियासी जमीन तैयार करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इसी वजह से संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का दौरा अहम माना जा रहा है। संघ अपनी हिंदुत्व की विचारधारा को खासतौर पर दलितों और आदिवासियों के बीच पहुंचाने की तैयारी में जुटा है, जहां अब तक उसकी बात नहीं पहुंच सकी है। दलित बस्तियों में सामाजिक समरसता के कार्यक्रम और भोज भी

इसी का हिस्सा हैं। इसके अलावा संघ गांवों में अपनी विचारधारा का विस्तार कर रहा है, ताकि जिन गांवों तक उसकी बात नहीं पहुंच सकी है, वहां भी माहौल बनाया जा सके।

सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में 19 और 20 को होने वाली बैठक में भाजपा की ओर से एक बजे से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल मौजूद रहेंगे। बैठक में भाजपा और संघ के साथ मिलकर काम करने पर चर्चा होगी। खासतौर पर 26 सितंबर से शुरू हो रहे बूथ सशक्तीकरण अभियान को लेकर चर्चा होगी। इसमें नए वोटर बनवाने के लिए हर बूथ पर संघ के स्वयंसेवकों की भी मदद ली जाएगी। कुछ सूत्रों का कहना है कि यह बैठक इस लिए भी महत्वपूर्ण है कि भाजपा आलाकमान निगम और आयोगों में कार्यकर्ताओं का समायोजन करने जा रही है, इसमें संघ कार्यकर्ताओं का भी समायोजन करने की योजना है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी ब्रजेश पाठक के अलावा सरकार के कुछ विभागों में मंत्रियों को भी बुलाया जा सकता है। इस दौरान संघ के आनुषांगिक संगठनों के साथ भी मंथन करके अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं की समस्याओं पर चर्चा होगी।

संघ प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम की बात की जाए तो वह 22 को लखनऊ पहुंचने के बाद प्रांत कार्यकारिणी, क्षेत्रीय कार्यकारिणी के साथ बैठक करेंगे इसमें अलग-अलग सत्र में जिला, विभाग प्रचारक और क्षेत्र प्रचारक मौजूद रहेंगे। इसमें वह यूपी में चल रहे संघ के कामों की समीक्षा करेंगे। संघ की योजना अब गांवों के साथ दलित और आदिवासी बस्तियों तक पहुंचने की है। बैठक का मुख्य एजेंडा यही है कि संघ के कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि कैसे वह दलितों, आदिवासियों और नए गांवों तक पहुंचें। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी बताते हैं कि आरएसएस विचारधारा के जरिए भी नए लोगों तक पहुंचता है। इसमें सबसे पहले संघ अपने मुख्य काम शाखा विस्तार पर फोकस करेगा। कुछ लोग जो सीधे संघ की रोज लगने वाली शाखा में नहीं आ पाते, उन्हें सामाजिक कामों के जरिए जोड़ा जाएगा। दलितों और आदिवासियों के बीच पैठ बढ़ाने के लिए वहां सामाजिक समरसता भोज, भजन संध्या, नशा मुक्ति के कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। संघ ने पहली बार घुमंतू जातियों पर भी फोकस किया गया है। इनमें नट, वनटांगिया और आदिवासियों के बीच भी नशा मुक्ति अभियान जैसे सोशल वर्क भी संघ करेगा। पहली बार आरएसएस ने हाल ही में खत्म हुए अपने ट्रेनिंग कैंपों में शताब्दी विस्तारक निकाले हैं। इन विस्तारकों के जिम्मे यही काम दिया गया है। वे रोज नए लोगों और नई जातियों से संपर्क करेंगे। संघ भले ही सीधे तौर पर बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहा है, पर हिंदुत्व की चर्चा और दलित बस्तियों में सामाजिक समरसता के आयोजनों के जरिए वह बीजेपी के लिए माहौल ही बनाएगा।

बुंदेलखंड के बुंदेला परिवार का नया राजनीतिक दाँव कितना कारगर सिद्ध होगा?

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर में स्थित बुंदेलखंड आजकल काफी सुर्खियों में है। एक वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली से सटी औद्योगिक नगरी नोएडा के गठन के 47 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नोएडा की ही तर्ज पर बुंदेलखंड का विकास करने के लिए इस क्षेत्र में नोएडा से भी आकार में बड़ा एक और नया औद्योगिक शहर बनाने का निर्णय लिया है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के नाम से नया औद्योगिक शहर झांसी-ग्वालियर मार्ग बसाया जाएगा। योगी सरकार द्वारा 12 सितंबर 2023 को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। खास बात ये है कि बीडा का आकार नोएडा से भी बड़ा होगा। नोएडा का गठन 13 हजार हेक्टेयर जमीन से किया गया था। बीडा का गठन करीब 14 हजार हेक्टेयर जमीन से किया जा रहा है। बीडा के लिए सरकार पहले चरण में 5000 करोड़ रुपये की राशि देगी। योगी सरकार का यह फैसला निश्चित ही तौर पर मील का पत्थर साबित होगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र में खुशहाली आयेगी।

दूसरी वजह पर गौर किया जाए तो इस समय बुंदेलखंड की सियासत में भी उबाल आया हुआ है क्योंकि यूपी की सियासत में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाला सुजान सिंह बुंदेला के परिवार का एक सदस्य यूपी की राजनीति से किनारा करके मध्य प्रदेश की सियासत में अपनी किस्मत आजमाने जा रहा है। यह सदस्य दो बार सांसद रह चुके सुजान सिंह बुंदेला के पुत्र चंद्रभूषण बुंदेला हैं। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भले ही कुछ ज्यादा नहीं चल पाएं हों लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस को चंद्रभूषण सिंह बुंदेला में काफी उम्मीदें नजर आ रही हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जैसे ही चंद्रभूषण सिंह को मध्य प्रदेश कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई, उसी के तुरंत बाद उन्हें पार्टी में उच्च पद और विधान सभा चुनाव लड़ने के लिए एक सीट से टिकट भी थमा दिया गया। बुंदेला पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कलमनाथ ने काफी विश्वास जताया है।

सवाल उठ रहा है जो चंद्रभूषण सिंह बुंदेला यूपी में सपा-बसपा के टिकट पर विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाए तो मध्य प्रदेश में वह कांग्रेस के लिए कैसे फायदे का सौदा हो सकते हैं। बाहुबली बसपा नेता चंद्रभूषण सिंह बुंदेला ने हाल ही में कमलनाथ के कहने पर कांग्रेस का हाथ थामा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद बुंदेला ने कहा कि मैंने घर वापसी की है। मेरे परिवार का डीएनए कांग्रेस का है। मैं और मेरे समर्थक पूरी ताकत से कांग्रेस की सरकार बनवाने के लिए काम करेंगे। चन्द्रभूषण मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव में सागर जिले के खुरई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं। ललितपुर सागर के खुरई विधानसभा क्षेत्र से लगा हुआ है। बुंदेला परिवार की अच्छी खासी रिश्तेदारी खुरई विधानसभा क्षेत्र में भी है। माना जा रहा है कि पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे के कांग्रेस छोड़ने के बाद वे खुरई में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के विरुद्ध कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस को इस विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी तक नहीं मिला था। ऐसे में कांग्रेस द्वारा चंद्रभूषण पर काफी गंभीर जिम्मेदारी डाली गई है।?

चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा बुंदेला के सितारे भले ही यूपी के चुनावी रण में नहीं

शेष पृष्ठ 22 पर

नये भारत के निर्माता हैं कर्मयोद्धा और प्रधान सेवक नरेन्द्र मोदी

ललित गर्ग

एक महान् कर्मयोद्धा के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजनैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सामरिक और आर्थिक सशक्तता की छाप छोड़ते हुए भारत को विश्वगुरु बनाने को तत्पर है, यह इतिहास के निर्माण का भाव है। निश्चित ही उनकी दृष्टि एवं दिशा भारत के नवशिल्प का आधार है। उन्होंने अंधेरों, अवरोधों एवं अक्षमताओं से संघर्ष करने की एक सार्थक मुहिम वर्ष 2014 में शुरू की। वे राजनीति में शुचिता के प्रतीक, अध्यात्म एवं विज्ञान के समन्वयक, कुशल राजनेता, प्रभावी प्रशासक, विलक्षण व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके 73वें जन्म दिवस पर सुखद एवं उपलब्धिभरी प्रतिध्वनियां सुनाई दे रही है, जिनमें नये भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के अमृतमय स्वर गूंज रहे हैं। हमने हाल ही में उनके नेतृत्व में भारत की अध्यक्षता में हुई जी-20 के समिट में विश्व मंच पर भारत की अमिट छाप छोड़ी है। उनका करिश्माई व्यक्तित्व एवं कृतित्व ही है कि नयी दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के घोषणापत्र पर आम सहमति बनी। वैश्विक विश्वास की कमी को पाटने तथा दुनिया में भरोसा विकसित करने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। उनके जीवन का प्रत्येक पल नये आयाम एवं नयी दिशाएं उद्घाटित करता रहा है, हमने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के मन्दिर के शिलान्यास का दृश्य देखा तो भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर होते हुए देख रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार के 9 वर्ष पूरे हो गए। इस दौरान उनके अनेकों यशस्वी कीर्तिमानों एवं उपलब्धियों में जो दो विशेष उपलब्धियां भारत के हर नागरिक के मन को अधिक छूती हैं, उनमें पहली है दुनिया में 'भारत का इकबाल' स्थापित होना। दूसरी-देश के भीतर 'भारत भी कर सकता है' भावना का संचार होना। अर्थात 'सब चलता है' वाला दृष्टिकोण अब भूतकाल के गर्त में है।

नरेन्द्र मोदी ने उद्देश्यपूर्ण जीवन जीकर जो ऊंचाइयां एवं उपलब्धियां हासिल की हैं, वे किसी कल्पना की उड़ान से भी अधिक है। अपने जीवन के सार्थक प्रयत्नों से उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि साधारण पुरुष वातावरण से बनते हैं, किन्तु महामानव वातावरण बनाते हैं। समय और परिस्थितियां उनका निर्माण नहीं करती, वे स्वयं समय और परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। साधारण पुरुष जहां अवसर को खोजते रहते हैं, वहां मोदी जैसे महापुरुष नगण्य अवसरों को भी अपने कर्तृत्व की छेनी से तराश कर उसे महान् बनाते हैं। उम्र के जिस मोड़ पर व्यक्ति पूर्ण विश्राम की बात सोचता है, उस स्थिति में मोदी जैसे राष्ट्रनायक नव-निर्माण, नव-सृजन करने एवं दूसरों को प्रेरणा देने में अहर्निश लगे हैं। विरोध को समभाव से सहकर वे जिस प्रकार उसे विनोद के रूप में बदलते रहते हैं। निश्चित ही एक प्रेरक पृष्ठ हैं नरेन्द्र मोदी।

नरेन्द्र मोदी के प्रभावी एवं चमत्कारी नेतृत्व में हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद वास्तविक आजादी का स्वाद चखने लगे हैं, आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रीयवाद, अलगावाद की कालिमा धूल गयी है, धर्म, भाषा, वर्ग, वर्ण और दलीय स्वार्थों के राजनीतिक विवादों पर भी नियंत्रण हो रहा है।

शेष पृष्ठ 23 पर

पृष्ठ 21 का शेष

चमक पाए हों, लेकिन बुंदेलखंड की राजनीति में वह मजबूत पकड़ रखते हैं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक रही है। गुड्डू बुंदेला के पिता सुजान सिंह बुंदेला झांसी लोकसभा सीट से 1984 और 1999 में दो बार सांसद रहे हैं। इसी वर्ष मार्च में सुजान सिंह बुंदेला का निधन हो गया था। बात सुजान के बेटे चंद्र भूषण सिंह गुड्डू राजा की बात की जाए तो वह पहले समाजवादी पार्टी में रहे हैं। बताया जाता है कि वे अखिलेश यादव के साथ विदेश में पढ़े थे, पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया, लेकिन वे चुनाव हार गए। इसके बाद जब अखिलेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने गुड्डू बुंदेला का टिकट काट दिया, जिसके बाद वे बसपा में चले गए थे, लेकिन वहां भी ज्यादा करिश्मा नहीं दिखा पाए और चुनाव हार गए। अब कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय ने बुंदेलखंड की चुनावी रणनीति को देखते हुए चंद्रभूषण को मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव से एन पहले कांग्रेस में एंट्री दिलाई है। इस तरह से यूपी के ललितपुर की सियासत में सक्रिय रहने वाले बुंदेला अब एमपी की राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। उन्होंने बसपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। माना जा रहा है कि गुड्डू राजा बुंदेला खुरई से कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह खुरई से सांसद हैं, ऐसे में अगर गुड्डू बुंदेला खुरई से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है।

बहरहाल, बुंदेला परिवार की सियासत के साथ पारिवारिक पृष्ठभूमि भी काफी उठा-पटक वाली रही है। एक तरफ बुंदेला परिवार ने राजनीति में नाम कमाया तो इस दौरान परिवार के बीच का पारिवारिक झगड़ा भी खूब सुर्खियां बटोरता रहा। बुंदेलखंड की राजनीति पर पकड़ रखने वाले जानते हैं कि करीब तीन दशक पहले तक बुंदेलखंड स्थित ललितपुर की राजनीति में ग्रामसभा की छोटी पंचायत से लेकर लखनऊ व दिल्ली तक बुंदेला बंधुओं का दबदबा था। बड़े दाऊ के नाम से पहचाने जाने वाले सुजान सिंह बुंदेला दो बार सांसद चुने गए। वहीं उनके भाई वीरेंद्र सिंह बुंदेला व पूरन सिंह बुंदेला कई बार विधायक बनने के बाद मंत्री बने। दस वर्ष पूर्व तीनों भाइयों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो गई थी, इसी को लेकर धीरे-धीरे भाइयों के बीच दूरियां और बढ़ती गईं। एक समय ऐसा आया कि एक-दूसरे के घर आना-जाना बंद हो गया।

पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह बुंदेला के पुत्र संजू राजा की हत्या के बाद भी दोनों के बीच दूरियां कम नहीं हुईं। स्थिति यह हो गई कि पैतृक गांव डोंगराकलां की प्रधानी के चुनाव में अलग-अलग प्रत्याशी खड़े किए जाने लगे। इस स्तर तक पहुंचे विरोध की वजह से इनकी राजनीतिक पकड़ लोगों के बीच से घटने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद सुजान के पुत्र चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा 2012 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए तो इसकी जानकारी पाते ही पूर्व मंत्री वीरेन्द्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में कूद पड़े। जातिगत समीकरणों को देखा जाए तो जनपद के क्षत्रिय व अन्य जातियों के मतदाता अधर में फंस गए। परिणामस्वरूप चंद्रभूषण सिंह बुंदेला लगभग दस हजार मतों से पराजित हो गए। वीरेंद्र सिंह बुंदेला को लगभग उन्नीस हजार मत मिले थे।

पृष्ठ 22 का शेष

इन नवनिर्माण के पदचिन्हों को स्थापित करते हुए कभी हम मोदी के मुख से स्कूलों में शोचालय की बात सुनते हैं तो कभी गांधी जयन्ती के अवसर पर स्वयं झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करते हुए उन्हें देखते हैं। मोदी कभी विदेश की धरती पर हिन्दी में भाषण देकर राष्ट्रभाषा को गौरवान्वित करते हैं तो कभी मेक इन इंडिया का शंखनाद कर देश को न केवल शक्तिशाली बल्कि आत्म-निर्भर बनाने की ओर अग्रसर करते हैं। नई खोजों, दक्षता, कौशल विकास, बौद्धिक संपदा की रक्षा, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन, श्रेष्ठ का निर्माण-ये और ऐसे अनेकों सपनों को आकार देकर सचमुच मोदीजी लोकतंत्र एवं राष्ट्रीयता को सुदीर्घ काल के बाद सार्थक अर्थ दे रहे हैं।

नरेन्द्र मोदी एक कर्मयोद्धा हैं, विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं उनके नेतृत्व में सरकार और सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक/एयर स्ट्राइक कर जबरदस्त पराक्रम का प्रदर्शन कर दिखाया है कि भारत की रक्षा शक्ति दुनिया के किसी विकसित देश से कम नहीं है। भारत पारंपरिक लड़ाई के साथ-साथ मॉडर्न लड़ाई में दुनिया की पेशेवर सेनाओं में से एक है। भारतीय जवानों द्वारा पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर देना भारत की बड़ी शक्ति एवं सामर्थ्य का परिचायक है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे बड़ा एवं साहसिक ऐतिहासिक फैसला जम्मू-कश्मीर को लेकर लिया जो जनसंघ के जमाने से उसकी प्राथमिकता रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ-साथ राज्य को दो हिस्सों में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ। मोदी सरकार के फैसले के बाद कश्मीर में एक देश, एक विधान और एक निशान लागू हो गया है। मोदी की विकास की योजनाएं, नीतियां, सिद्धान्त और संकल्प सही परिणामों के साथ सही लोगों तक पहुंच रहे हैं।

मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से शहर में हुआ था। वे 'अति पिछड़ा वर्ग' परिवार से आते हैं, जो समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों में से है। वह बेहद गरीब, लेकिन प्यार देने वाले परिवार में पले बड़े। जीवन की शुरुआती कठिनाइयों ने न केवल उन्हें कड़ी मेहनत के मूल्य को सिखाया बल्कि उन्हें आम लोगों के कष्टों से भी अवगत

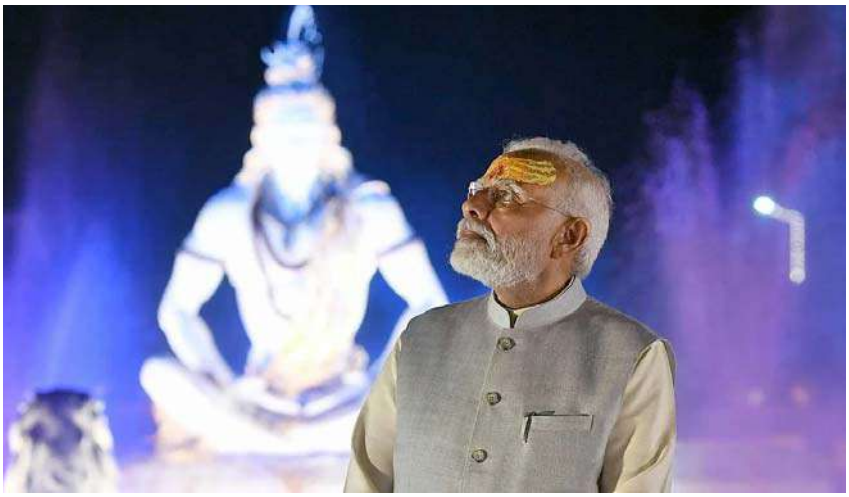

कराया। आम जन की गरीबी ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही लोगों और राष्ट्र की सेवा में डूबने के लिए प्रेरित किया। अपने प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साथ काम किया, जो राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित एक राष्ट्रवादी संगठन है और बाद में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करने के लिए खुद को राजनीति में समर्पित किया।

नरेंद्र मोदी विश्व के चर्चित एवं शिखर नेता होकर भी जन-जन के एवं जमीनी नेता हैं और वे आमजन के बीच जाने, उनकी समस्याओं को हल करने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए समर्पित हैं। लोगों के बीच रहने, उनके साथ खुशियाँ साझा करने और उनके दुखों को दूर करने से ज्यादा कुछ भी उनके लिए संतोषजनक नहीं है। जमीनी स्तर पर तो उनका लोगों के साथ एक मजबूत व्यक्तिगत जुड़ाव तो है ही साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी उनकी मजबूत उपस्थिति है। राजनीति से परे नरेंद्र मोदी को लिखना पसंद है। उन्होंने कई कविता और कई किताबें लिखी हैं। उनके विचारों में राष्ट्रवादी, सामाजिक एवं व्यक्तिगत उन्नयन के क्रांति-बीज मिलते हैं। मन की बात कार्यक्रम में वे राष्ट्र उन्नयन, सामाजिक-क्रांति, आडम्बरप्रधान विकृत प्रवृत्तियों को बदलने एवं समाज-राष्ट्र-निर्माण में उल्लेखनीय कार्य करने के उपाय निर्दिष्ट करते हैं। वे अपने दिन की शुरुआत योग से करते हैं। योग उसके शरीर और दिमाग को मजबूत बनाता है और तेज गति चलने वाली दिनचर्या में शांति का भाव पैदा करता है। वे प्रकृति प्रेमी हैं।

नरेन्द्र मोदी विश्वनेता के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन्हें अनेक देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान प्रदत्त किये हैं। सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'किंग अब्दुलअजीज सैश' से तो रूस के शीर्ष सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टले सम्मान', फिलिस्तीन के 'ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन' सम्मान, अफगानिस्तान के 'अमीर अमानुल्ला खान अवॉर्ड', यूएई के 'जायेद मेडल' और मालदीव के 'निशान इज्जुद्दीन' सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को शांति और विकास में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार भी दिया गया।

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं और देश का सिर सम्मान से ऊंचा उठा और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। मोदी-दर्शन कहता है-जो आदमी अभय से जुड़ता है वह अकेले में जीने का साहस करता है। जो अहिंसा को जीता है वह विश्व के साथ मैत्री स्थापित करता है। जो अनेकांत की भाषा में सोचता है वह वैचारिक विरोधों को विराम देता है। उनका आत्मविश्वास उन्हें नित-नवीन रोशनी देता है। यही पुरुषार्थ और निष्ठा उनको सीख और समझ देती है कि सिर्फ कुर्सी पर बैठने वालों का कर्तृत्व ही कामयाबी पर नहीं पहुंचता, सामान्य कागजों पर उतरने वाले आलेख भी इतिहास की विरासत बनते देखे गये हैं। समय से पहले समय के साथ जीने की तैयारी का दूसरा नाम है मोदी। दुनिया का कोई सिकंदर नहीं होता, वक्त सिकंदर होता है इसलिए जरूरी है कि हम वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखें।

एक नहीं कई टुकड़ों में बँटेगा पाकिस्तान, आतंकवाद का गढ़ अब पूरी तरह ढहने की कगार पर है

सुरेश हिंदुस्तानी

वर्तमान में पाकिस्तान में जिस प्रकार के स्वर मुखरित हो रहे हैं, उसके निहितार्थ लगाए जाएं तो यही परिलक्षित होता है कि पाकिस्तान की जनता अब अपने ही उन नीति नियंताओं का विरोध करने पर उतारू हो गए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही राजनीतिक दुष्चक्र में गोता लगाने वाले पाकिस्तान के शासकों ने केवल अपने हित की राजनीति को ही प्रधानता दी। जिसके कारण न तो पाकिस्तान प्रगति कर सका और न ही वहां की जनता का जीवन स्तर ही बेहतर हो सका है। आज इस तथ्य को सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की जनता अनेक प्रकार की विसंगतियों का सामना कर रही है। महंगाई का आलम यह है कि जनता इसमें लगातार पिस रही है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं के आसमानी भाव ने जनता के माथे पर चिंता की लकीरें स्थापित कर दी हैं। अब पाकिस्तान में एक नई समस्या भी स्थापित हो रही है, जिसमें अब पाकिस्तान की जनता ही अपने शासकों को कोस रही है। इतना ही नहीं वहां की जनता के मुख से पाकिस्तान से आजादी प्राप्त करने की आवाजें सुनाई देने लगीं हैं। इससे हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी स्वयं की करनी के कारण टूट कर बिखर जाए।

वर्तमान में पाकिस्तान के कई प्रांतों में भारतीयता की झलक देखने को मिल रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान स्वाभाविक रूप से आज भी भारत का ही अंग है। पाकिस्तान ने बार-बार कश्मीर बोला, भारत ने हमेशा सहन किया। इसके बाद भारत ने एक बार ब्लूचिस्तान के नागरिकों की भावनाओं को व्यक्त किया तो चीन और पाकिस्तान की भौंहें तन गईं। पूरा विश्व इस बात को भली भांति जानता है कि आज बलूचिस्तान, गिलगित और बाल्टिस्तान में जिस प्रकार से मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। इन स्थानों पर अंदर ही अंदर पाकिस्तान के विरोध में वातावरण बना हुआ है। कुछ लोगों ने खुलकर विरोध करना प्रारंभ कर दिया है और कुछ लोग पाकिस्तान के दमनकारी रवैये के कारण डरे सहमे हुए हैं। अगर पाकिस्तान के इन क्षेत्रों के लोगों की भावनाओं को समझा जाए तो यह क्षेत्र किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते।

भारत में जिस प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, उसी तरह की बोलने की आजादी पाकिस्तान में भी होती तो संभवत: आज पूरे पाकिस्तान में ही विरोधी स्वर सुनाई दे रहे होते। सिंध और बलूचिस्तान की जनता की ओर से जहां भारत में शामिल होने के स्वर सुनाई देने लगे हैं। इतना ही नहीं इन प्रदर्शनकारियों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का खुलकर समर्थन भी किया है। आगे चलकर यह भी हो सकता है कि बलूचिस्तान और सिंध की तर्ज पर पाकिस्तान के पंजाब में भी आजादी की मांग उठने लगे। क्योंकि पंजाब के कई लोग अपने आपको आज भी स्वाभाविक रूप से भारत का हिस्सा ही मानते हैं। वहां भारतीय संस्कृति के अवशेष बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं वहां के जनजीवन में भी भारतीयता की झलक दिखाई देती है।

पाकिस्तान में आज जो हालात दिखाई दे रहे हैं, वह केवल आतंकी आकाओं की बढ़ती हुई सक्रियता का ही परिणाम कहा जाएगा। कई क्षेत्रों में बेरोजगारी और भुखमरी के हालात हैं। पाकिस्तान ने इस समस्या के समाधान के लिए किसी प्रकार के प्रयास नहीं किए। इसके विपरीत आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पूरा समर्थन दिया। वर्तमान में पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि लोग आतंकवाद का विरोध करना भी चाहें तो भी नहीं कर सकते। ऐसा करने पर आतंकवादी अपने ही नागरिकों पर अत्याचार करते हैं। जिसका दंश भोली भाली जनता को भोगना पड़ रहा है। पाकिस्तान की जनता पूरी तरह से आतंकवाद से त्रस्त आ चुकी है।

लम्बे समय से पाकिस्तान की दमनकारी अत्याचार को सहन कर रही वहां की जनता को जब लगा कि नरेन्द्र मोदी ने उनकी भावनाओं को समझा है, तो वह पूरी तरह से उनके साथ आने लगे हैं। इसके साथ ही कश्मीर की बात करें तो वहां के वातावरण को बिगाड़ने में पाकिस्तान का पूरा हाथ रहा है। यहां पर एक बात तो साफ है कि पूरी समस्या के लिए पाकिस्तान ही दोषी है, फिर भी उलटा चोर कोतवाल को डांटे वाली तर्ज पर पाकिस्तान की सरकार चल रही है। पाकिस्तान के अपने प्रांतों में वर्तमान में जो हालत है, उसके लिए पाकिस्तान के सरकारी मुखिया और आतंकवाद फैलाने वाले संगठन ही जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान के विरोध में पाकिस्तानियों के खड़े होने का आशय यही है कि वहां का हर व्यक्ति आतंकवाद का समर्थन नहीं करता।

आज बलूचिस्तान में पाकिस्तान से आजादी की मांग करने के लिए जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां पहले तो इस बात को समझना चाहिए कि बलूचिस्तान क्या है? तो इसका जवाब यही है कि बलूचिस्तान को आजादी के समय अलग देश की मान्यता मिली थी। यह पाकिस्तान का स्वाभाविक हिस्सा नहीं था। पाकिस्तान ने हमला करके बलूचिस्तान पर कब्जा किया था। तब से ही बलूचिस्तान के नागरिक पाक की ज्यादतियों के विरोध में आवाज उठाते रहे हैं। इसलिए यह कहना कि यह भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कारण हो रहा है, किसी भी रूप से सही नहीं है। यह बात सही है कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर बेशर्मी की हदें पार करने वाला व्यवहार करता आया है, इसलिए उससे कश्मीर के मामले में अच्छे व्यवहार की कल्पना करना निरर्थक ही है। बार-बार पराजय झेलने के बाद भी उसकी भूमिका में कोई सुधार नहीं आया है।

अब सवाल यह आता है कि जिस प्रकार से बलूचिस्तान और सिंध में पाकिस्तान से आजाद होने की आवाजें उठ रही हैं, उसमें भारत की क्या भूमिका रहेगी। पाकिस्तान के प्रांतों में आजादी के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान भविष्य में तीन या चार हिस्सों में विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए पाकिस्तान के चार हिस्से बनते हैं, तब बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब देश पाकिस्तान के विरोध में रहेंगे। तब पाकिस्तान एक दम कमजोर हो जाएगा और फिर उसकी ओर से फैलाए जा रहे आतंकवाद की आग में वह स्वयं ही झुलस जाएगा।

बुलन्द भारत की बुलन्द आवाज मोदी का डंका बजा

दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके निर्णायक नेतृत्व और वैश्विक दक्षिण की आवाज उठाने के लिए सराहना की। विश्व नेताओं ने भी भारत के आतिथ्य की सराहना की और एक सफल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिल खोलकर सराहना की।

भारत की जी20 की अध्यक्षता से कई ठोस नतीजे सुनिश्चित होने के बीच यहां दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके निर्णायक नेतृत्व और वैश्विक दक्षिण की आवाज उठाने के लिए सराहना की। न्यूज एजेंसी के मुताबिक विश्व नेताओं ने भी भारत के आतिथ्य की सराहना की और एक सफल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए प्रधान मंत्री मोदी की प्रशंसा की।

सूत्रों के अनुसार एक बैठक में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि भारत के नेतृत्व में, हमने देखा है कि हम एक साथ आ सकते हैं, ऐसे समय में जब यह वास्तव में मायने रखता है। जब आप 'भारत मंडपम' में घूमते हैं और इसमें डिस्पले देखते हैं तो हम पता चलता है कि पीएम मोदी, डिजिटल पहल

शेष पृष्ठ 26 पर

अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी छाये मोदी

अंतरराष्ट्रीय मीडिया भारत में जी-20 के सफल आयोजन की तारीफ करने के साथ-साथ पीएम मोदी का भी गुणगान कर रही है। विश्व मीडिया ने कहा कि जी 20 शिखर सम्मेलन में रूस-यूक्रेन युद्ध पर प्रमुख मतभेदों को दूर करते हुए सदस्य देशों के शनिवार को नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन को अपनाया जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक अप्रत्याशित सफलता है। हालांकि, इसमें यूक्रेन पर रूस के हमले का जिक्र करने से परहेज किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक भारत ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ वार्ताओं के जरिये यूक्रेन के विवादास्पद मुद्दे पर जी 20 देशों के बीच एक अप्रत्याशित आम सहमति बनाने में कामयाब रहा। नयी दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय जी 20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं के बीच घोषणापत्र को लेकर सहमति बनी। घोषणापत्र में जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास पर साझा विचार रखे गये, लेकिन इसमें यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा करने से बचा गया।

इसी कड़ी में दुबई स्थित मीडिया संगठन, गल्फ न्यूज ने इस पहलू पर जोर दिया कि कैसे 18वें जी20 शिखर सम्मेलन ने सद्भाव और विविधता में दुनिया को आकार दिया। एंथनी अल्बानी ने जी 20 शिखर सम्मेलन के समापन के साथ समझौते को कमजोर करने की सराहना की। वहीं, अल जजीरा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रूस ने संतुलित घोषणा की सराहना की है क्योंकि जी20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी कहा कि भारत की बैठक समाप्त होने पर अमेरिका , रूस ने जी 20 शिखर सम्मेलन की घोषणा की प्रशंसा की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रविवार को कहा था कि इस साल के जी20 शिखर सम्मेलन ने साबित कर दिया है कि समूह अभी भी जलवायु संकट, नाजुकता और संघर्ष के सबसे गंभीर मुद्दों का समाधान निकाल सकता है।

पृष्ठ 25 का शेष

और टेक्नोलॉजी क्या कर सकते हैं। इसके जरिए हमारे देशों के दूरदराज के कोनों में भी लोगों तक सेवाएं पहुंचाई जा सकती है।

शिखर सम्मेलन के दौरान जापानी प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा ने जी 20 का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की तो वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत की अध्यक्षता में रखी गई नींव के आधार पर जी 20 सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि शिखर सम्मेलन इस दुनिया के लिए आशीर्वाद साबित होगा।

सूत्रों के मुताबिक, कई नेताओं ने भी ग्लोबल साउथ की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की और अफ्रीकी संघ (एयू) को जी 20 का सदस्य बनाने के महत्वपूर्ण निर्णय की सर्वसम्मति से सराहना की। मोदी की सराहना करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अफ्रीकी संघ एक महत्वपूर्ण भागीदार है। आप (मोदी) हमें एक साथ ला रहे हैं, हमें एक साथ रख रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं कि हमारे पास चुनौतियों से मिलकर निपटने की क्षमता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा, मैं अफ्रीकन यूनियन को इस तालिका में लाने के लिए आपकी बुद्धिमत्ता के लिए आपको (मोदी) बधाई देती हूं।

वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने और वैश्विक दक्षिण की आवाज उठाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। जी20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह सभी जीवन के मूल्य और बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करने के महत्व को कायम रखता है।

कोमोरोस संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अज़ाली असौमानी ने भी उनकी उम्मीदवारी के समर्थन के लिए भारत को धन्यवाद दिया।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अफ्रीकन यूनियन को जी20 में शामिल कराने में भूमिका के लिए भारत की सराहना की, वहीं नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुटे ने ग्लोबल साउथ को समूह के केंद्र में रखने के लिए भारतीय राष्ट्रपति पद को धन्यवाद दिया।

वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने इस कार्यक्रम के आयोजन में सक्षमता के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, आज मैं भावुक हो गया, जब मैं प्रिय (महात्मा) गांधी को श्रद्धांजलि देने गया। मेरे राजनीतिक जीवन में गांधी का बहुत महत्व है। अहिंसा एक सिद्धांत है जिसका मैं पालन करता हूं।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम जो हासिल करेंगे उसके लिए लोग हमें याद रखेंगे और प्रधानमंत्री मोदी, आपने हमें %एक भविष्य% पर चर्चा करने के लिए यहां इकट्ठा किया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ ने जी20 में बहुत सफल परिणाम के लिए भारत के नेतृत्व की सराहना की और इस अवसर के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया।

शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले स्पेनिश प्रतिनिधि ने भी भारत के उत्कृष्ट नेतृत्व की सराहना की और प्रधान मंत्री मोदी के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। मैक्सिकन प्रतिनिधि ने जी20 के लिए अद्भुत व्यवस्था की प्रशंसा की, जबकि ओमान के प्रतिनिधि ने भारतीय आतिथ्य की सराहना की।

जी20 रात्रिभोज में प्रधान मंत्री मोदी से मुलाकात करने वाली आईएमएफ की प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ऐसे सफल जी20 सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। भारत का संदेश एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य सभी प्रतिनिधियों के बीच दृढ़ता से गूंजा है।

शिखर सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए वर्ल्ड बैंक के प्रमुख अजय बंगा ने कहा, मैं भारत और उसके नेतृत्व के साथ-साथ सभी जी20 नेताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए बधाई देता हूं कि इतनी शानदार घोषणाएं की गईं।

भारत-मध्यपूर्व-यूरोप इकॉनमी कॉरिडोर के आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक मायने को ऐसे समझिए

कमलेश पांडे

वसुधैव कुटुम्बकम से लेकर पूंजीवाद तक के लिए मुफीद ग्लोबल विलेज की अवधारणा के दृष्टिगत तेजी से बदलती दुनियादारी के बीच जी 20 देशों के नई दिल्ली घोषणा पत्र के अलावा प्रस्तावित भारत-मध्यपूर्व-यूरोप इकॉनमी कॉरिडोर की जो घोषणा हुई है, उसके वैश्विक व क्षेत्रीय आर्थिक और सामरिक मायने अहम हैं। निकट भविष्य में इनके आकार लेते ही राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मायने भी प्रभावित होने लगें तो कोई हैरत की बात नहीं होगी।

सच कहूं तो आरएसएस और भाजपा की जो नई रीति-नीति स्थापित हो रही है, उसके दृष्टिगत भी यह एक बेहद अहम फैसला है। जिससे चाहे अखंड भारत का स्वप्न हो या फिर वसुधैव कुटुम्बकम का, इस प्रस्तावित वैश्विक आर्थिक गलियारे से दोनों बखूबी सधेंगे, बशर्ते कि 2024 में मोदी श्री सरकार पुन: सत्ता हासिल कर ले। बताया गया है कि भारत से यूरोप तक प्रस्तावित भारत-मध्यपूर्व-यूरोप इकॉनमी कॉरिडोर को दुनिया के आठ देश मिलकर बनाएंगे, जो भारत से इजरायल होते हुए यूरोप तक जाएगा।

मसलन, इस कॉरिडोर के निर्माण में भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी की भागीदारी होगी। ये वो देश हैं, जो चीन के मुकाबले भारत को अपने ज्यादा करीब मानते आए हैं-लोकतांत्रिक और आर्थिक दोनों नजरिए से। इसलिए प्रस्तावित भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा जी-20 शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली का वह ऐतिहासिक फैसला है, जिसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी।

जानकारों की राय में, इस नए गलियारे के फैसले से भू-राजनीतिक रूप से न केवल एशिया और यूरोप के देश एक दूसरे के बेहद करीब आएंगे, बल्कि अशांत मध्यपूर्व में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयत्न भी करेंगे। इस नजरिए से देखा जाए तो यह एक बेहतर, अधिक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण भविष्य के लिए एक साथ काम करने के लिए संकल्प लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बेजोड़ नमूनों में से एक है।

नया गलियारा भारत के प्रतिद्वंद्वी देश चीन के वन बेल्ट, वन रोड परियोजना के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक भारतीय विकल्प के रूप में भी आंका जाने लगा है। इससे चीन व उसके समर्थक देशों को मिर्ची भी लगी होगी, लेकिन मोदी डिप्लोमेसी के सामने न तो किसी की चलती है और न ही कुछ चलने देने के लिए कोई कमी अपनी नीति में वो छोड़ते हैं, जो भारत के बढ़ते वैश्विक सामर्थ्य का प्रतीक बन चुके हैं।

बता दें कि बीआरआई की परिकल्पना 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी, जो वर्ष 2016 से वन बेल्ट वन रोड परियोजना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के नाम से जाना जाता है। यह एशिया, यूरोप व अफ्रीका के बीच भूमि और समुद्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चीन की परियोजनाओं का एक समूह है। जिसे अब भारत की बदलती सशक्त कूटनीति व रणनीति से कड़ी टक्कर मिल रही है।

भारत से यूरोप तक प्रस्तावित भारत-मध्यपूर्व-यूरोप इकॉनमी कॉरिडोर को चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसे दक्षिण एशिया, मध्यपूर्व और अफ्रीका के कई देशों ने अपनाया है। इसलिए अब बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि नया प्रस्तावित आर्थिक गलियारा किस गति से लागू किया जाता है और इसके सामूहिक ध्येय की प्रतिपूर्ति में कितनी ईमानदारी बरती जाती है।

भारत से मध्यपूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक ही कहा है कि इससे वैश्विक बुनियादी ढांचे, निवेश के लिए साझेदारी, आवाजाही और सतत विकास को एक नई दिशा मिलेगी। इतने बड़े कदम के साथ हम भविष्य के विकास के लिए बीज बो रहे हैं।

शेष पृष्ठ 28 पर

पृष्ठ 27 का शेष

जो आपसी विश्वास मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभायेगा। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक ढांचे और निवेश के लिए साझेदारी (पीजीआईआई) के जरिए ग्लोबल साउथ देशों में बुनियादी ढांचे का अंतर भरने में हम बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में एक साथ काम करने के इच्छुक थे, किंतु मध्य-पूर्व में दोनों को मिलकर काम करने की बहुत कम सम्भावना थी। लिहाजा भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा पर दोनों देशों ने हाथ मिला लिया है, जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं, अमेरिकी अधिकारी भी यह मानते हैं कि इस मेगा कनेक्टिविटी परियोजना से अंतर-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अरब प्रायद्वीप में राजनीतिक गहमागहमी में कमी आएगी। इससे इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता भी आएगी।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह गलियारा अरब प्रायद्वीप के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी को और गहरा करेगा। क्योंकि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ तेजी से राजनीतिक और रणनीतिक सम्बन्ध बढ़ाए हैं। वहीं, इस गलियारा से पश्चिम से भारत की जमीनी कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी, जो पाकिस्तान की जमीनी आवाजाही के अड़ंगे को बेअसर कर देगा। वहीं, चूंकि तेहरान (ईरान) के साथ भारत के सम्बन्ध अच्छे हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के साथ उसका टकराव जगजाहिर है। ऐसे में ईरान से यूरेशिया तक बनने जा रहे इस आर्थिक गलियारे से भारत की व्यवसायिक गतिविधियों पर सकारात्मक असर पड़ने की सम्भावना है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत से यूरोप तक प्रस्तावित भारत-मध्यपूर्व-यूरोप इकॉनमी कॉरिडोर यूरोप की सक्रियता का प्रतीक है। क्योंकि यूरोपीय संघ ने 2021-27 में दुनिया में बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च के लिए 300 मिलियन यूरो निर्धारित किये थे, जिसका समर्थन यूरोपीय संघ को, भारत, अरब व यूरोप को प्रमुख हितधारक बना देगा। यही वजह है कि दुनिया के अन्य देशों ने भी भारत के इस सपने को साकार करने में न केवल अहम भूमिका निभाई है, बल्कि सार्वजनिक रूप से उसकी सराहना भी की है।

एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि प्रस्तावित आर्थिक कॉरिडोर को दुनिया के 8 देश मिलकर बनाएंगे। यह भारत से इजरायल और यूरोप तक जाएगा। आने वाली पीढ़ियां इस ऐतिहासिक फैसले को याद रखेंगी। उन्होंने आगे कहा कि, आर्थिक गलियारे के प्रमुख हिस्से के रूप में हम जहाजों और रेलगाड़ियों में निवेश कर रहे हैं। इससे व्यापार आसान होगा। तो दूसरी ओर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि, यह पहल वैश्विक हरित व्यापार मार्ग से सम्बंधित है।

वहीं, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस प्रस्तावित कॉरिडोर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इससे व्यापार में मजबूती आएगी और इसके साथ ही यात्रा के समय में कमी आएगी। वहीं, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आर्थिक कॉरिडोर की स्थापना के लिए यहां तक पहुंचने में अहम योगदान दिया है।

इसलिए समझा जा रहा है कि भारत से यूरोप तक प्रस्तावित भारत-मध्यपूर्व-यूरोप इकॉनमी कॉरिडोर दुनिया के लिए तरक्की की नई राह खोलेगा। इससे विभिन्न देशों के बीच न केवल पारस्परिक संपर्क बढ़ेगा, बल्कि व्यापार और रोजगार भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगा। स्वाभाविक है कि इससे महाद्वीपीय संस्कृति भी एक-दूसरे से प्रभावित होगी जो परस्पर आत्मसात की जाएगी। चूंकि भारतीय सभ्यता व संस्कृति की आत्मसात करने की क्षमता दूसरों से अधिक है, इसलिए नया गलियारा उसकी लोकप्रियता वृद्धि में भी सहायक हो सकता है।

पार्टी बदलना है...

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा 'उरतृप्त'

कद्दावर नेता अपने भूतपूर्व होने वाली पार्टी के मुखिया के सामने बैठे थे। उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाना जारी रखाङ्क ''देखिए मैं इस पार्टी का पुराना चावल हूँ। आप जानते भी हैं कि मेरे विचार पार्टी के लिए कितने काम आए हैं। इतना ही नहीं मेरे विचार काफी कीमती भी रहे हैं। चूँकि अब पार्टी का दबदबा कम हो गया है और आने वाले चुनावों में जीतने के आसार कम हैं, इसलिए पार्टी बदलने के बारे में विचार कर रहा हूँ। अत: आप से निवेदन है कि आप मेरे इन विचारों को अपने पास गिरवी रख लें। इसके बदल में मुझे केवल इतना आश्वासन दें कि जब भी पार्टी की स्थिति सुधर जाए तो मुझे पुन: जोड़ लें। जोड़ते समय केवल इस बात का ध्यान रखें कि बिना किसी आनाकानी के मुझे जोड़ लें। अब जो सौहार्द भाव तब भी उसी तरह भाव बना रहे। मेरे विचारों आपकी छाप है, पार्टी अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी इसमें हैं। किसी समय पार्टी में इनकी बड़ी कद्र थी। ये अभी भी अच्छी हालत में हैं, इसलिए मेरे लड़के को ये विचार देकर खुद दूसरी पार्टी में जाना चाहता हूँ। इससे लाभ यह होगा कि लड़का हार भी जाए तो मैं सत्ता वाली पार्टी में बना रहूँगा और यदि मैं हार गया तो बेटा सत्ता वाली पार्टी में बना रहेगा। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हम दोनों कहीं भी रहें हमारा लाभ बना रहेगा। विचार भी जीवंत रहेंगे।''

''ऐसा है कि पार्टी की स्थापना के समय में, मेरा मतलब है कि आरंभिक समय में मेरे बाऊजी बड़े इसी पार्टी के कार्यालय में बैठकर गप्प हाँका करते थे। उनकी गप्प ही आगे चलकर पार्टी की विचारधारा बनी। वहीं से वे विचार मुझ तक आए। इन्हें मैंने आगे चलकर लिख लिया। कभी बिखर न जाएँ इसके लिए अलमारी में संभालकर रख दिया। किंतु नई पार्टी में ज्वाइन करने में ये विचार अड़चन बन रहे हैं। अब यह मेरे किसी काम के नहीं हैं इसलिए.....।'' कद्दावर नेता ने अपनी सफाई दी।

''ठीक है..., अब आप अपने विचार अपने बेटे को देकर उसे हमारी पार्टी में ज्वाइन कराना चाहते हैं। क्या इसे अपने बेटे को न देकर किसी और को देते तो क्या दिक्कत आती। आपके साथ तो कई सारे कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी तो दे सकते थे?''

''चहता तो था कार्यकता को दे दूँ। बाद में ध्यान आया कि इतने साल बाद जब मैं बदल सकता हूँ तो वह कैसे नहीं बदलेगा। इसलिए राजनीति में विचारों का हस्तांतरण परिवारवाद के आधार पर होना चाहिए। इसीलिए मैंने अपने विचार बेटे को देने का निर्णय किया है।''

''और क्या चाहते हैं आप ?''

''देखिए ये बहुत कीमती विचार है। इन विचारों से देश में कई सरकारें बनी हैं और चलीं भी हैं। इस हिसाब से कीमत अमूल्य होना चाहिए लेकिन मैं मात्र अपने बेटे के लिए पार्टी का टिकट भल चाहूँगा।'' कद्दावर नेता ने अपना प्रस्ताव दिया।

''बेटे को टिकट!! ये सोचा भी कैसे आपने !?! अब आपके विचारों को यहाँ पूछता भी कौन है?''

''इसका अतीत देखिए मिस्टर पटेल, अगर आप इसके इतिहास पर गौर करेंगे तो आपको ये कीमत ज्यादा नहीं लगेगी।''

''देखिए मेरे पास सभी तरह के विचार पड़े हैं, जैसे गांधीवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी आदि-आदि। लेकिन आजकल इनको पूछने वाला भी नहीं आता है। सच कहूं तो मार्क्स की फटी कमीज या घिसे जूतों के ग्राहक मिल सकते हैं लेकिन विचारों के नहीं। सॉरी, ... मैं इसे नहीं रख पाउंगा।'' मुखिया ने विवशता बताई।

''देखिए आप सभी तरह के विचारों को खपाने में सक्षम हैं और इस मामले में आपकी ख्याति दूर दूर तक है। मैं सोचता हूं कि इसकी कद्र करने वाले आपके पास जरूर पहुंचेंगे।.... चलिए मेरे बेटे का न सही पत्नी को ही दे दीजिए।'' कद्दावर नेता ने नया प्रस्ताव किया।

''देखिए आपकी लोटा नीति आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले भी आप जैसे एक सज्जन इसी तरह का कुछ कर गए थे, न उन्होंने हमारा फायदा किया और न ही हम उनका फायदा कर पाए। इसलिए इस मामले में आपकी सहायता नहीं कर पाऊँगा।''

कद्दावर नेता इतना सा मुँह बनाए वहाँ से चलते बने। वहीं मुखिया इस बात की खुशी मना रहे थे वे बेवकूफ बनने से बच गए।

पहाड़ों पर है घूमने का मन तो चले आइए भोपाल, नेचर के साथ उठाएं एडवेंचर का लुत्फ

अनन्या मिश्रा

हिल स्टेशन का नाम आते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोपाल में कई हिल स्टेशन हैं। लेकिन बता दें कि भोपाल में परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकती हैं। यहां पर आपको घूमने के लिए कई ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपका भी पहाड़ों पर जाने का मन है तो आप भोपाल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको भोपाल के कुछ बेहतरीन हिल स्टेशनों के बारे में बताने जा रहे हैं। जहां पर आपको घूम कर एक अलग अनुभव होगा।

पचमढ़ी हिल स्टेशन

बता दें कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पचमढ़ी एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसी वजह से दुनियाभर से लोग यहां घूमने के लिए आते हैं। पचमढ़ी हिल स्टेशन घूमने के बाद आप उत्तराखंड और हिमाचल की खूबसूरती को भूल जाएंगे। पचमढ़ी केवल सड़क के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। भोपाल से पचमढ़ी हिल स्टेशन की दूरी करीब 159 किमी है। भोपाल से पचमढ़ी पहुंचने में आपको करीब 4 घंटे का समय लगेगा। आप यहां पर अपनी गाड़ी या बस से भी पहुंच सकते हैं।

मांडू हिल स्टेशन

मध्य प्रदेश में स्थित मांडू हिल स्टेशन रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। यहां पर घूमने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। बारिश के मौसम में मांडू हिल स्टेशन में हरियाली की मखमली सी चादर चढ़ जाती है। जिससे यहां पर घूमने का मजा दोगुना हो जाता है। यहां पर आप अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ आ सकते है। माढू में आपको घूमने के कई ऑप्शन मिल जाएंगे। भोपाल से मांडू पहुंचने के लिए आपको गाड़ी या फिर बस से जाना होगा।

पातालकोट हिल स्टेशन

पातालकोट हिल स्टेशन एक घाटी की तरह है। यहां पर मानसून में घूमने का मजा दोगुना हो जाता है। अगर आप इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको यहां पर

ट्रेकिंग का लुत्फ जरूर उठाना चाहिए। पहाड़ों के ऊपर से दिखने वाला अद्भुत नजारा आपके ट्रिप को शानदार बना देगा। भोपाल से इस हिल स्टेशन की दूरी 256 किमी है। आप अपनी कार से भी यहां पहुंच सकते हैं। भोपाल से पातालकोट जाने में करीब 5 घंटे का समय लगता है।

हनीमून डेस्टिनेशन के लिए परफेक्ट है ये जगह, हसीन वादियों में बिताएं रोमांटिक पल

अनन्या मिश्रा

भारत में अपने ऐतिहासिक इमारतों और प्राकृतिक नजारों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। भारत देश दुनियाभर के लोगों को कई खूबसूरत पहाड़ों और समुद्री जगहों की वजह से आकर्षित करता है। अगर पानी के किनारे बसी जगहों की बात करें तो आइलैंड जैसी जगहें भी लोगों को खूब भाती हैं। हालांकि अगर आइलैंड का नाम आते ही आपके दिमाग में मालदीव का ख्याल आता है, तो बता दें कि भारत में स्थिति अंडमान-निकोबार भी कम नहीं है।अंडमान-निकोबार बिलकुल मालदीव की तरह दिखता है। साथ ही यह लोगों का फेवरेट स्पॉट भी बन चुका है। जहां मालदीव में घूमने के लिए कपल्स लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। तो वहीं अंडमान में घूमने का खर्च बहुत कम आता है। ऐसे में अगर आप भी सस्ते में ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अंडमान एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको यहां पर आने वाले कुछ खर्चों के बारे में बताने जा रहे हैं।

अंडमान और निकोबार

बता दें कि अंडमान में करीब 300 द्वीप हैं। यह द्वीप हजारों साल पुराने हैं। यहां पर जारवा, सेंटिनली, ग्रेट अंडमानी, ओन्गे जैसी जनजातियों के लोग रहते हैं। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के अलावा जापान और भारत के लोगों के आने तक लोग प्राचीन समय से ही इन द्वीपों में निवास कर रहे हैं। द्वीपों की भूमि बांग्लादेश के शरणार्थियों को भी रहने के लिए दी गई थी। वहीं अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर वर्तमान में भी वैसी की वैसी है। यहां पर आपको ना तो आकर्षक मॉल मिलेंगे और ना ही मल्टीप्लेक्स थियेटर मिलेंगे। अंडमान में रहने वाले लोग आज भी वेस्टर्न कल्चर से कोसों दूर हैं।

43 वर्ष की हुई करीना कपूर

इस फिल्म से की थी अपने सिने करियर की शुरुआत

मुंबई। बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री करीना कपूर आज 43 वर्ष की हो गई हैं। 21 सितंबर 1980 को मुंबई में जन्मीं करीना कपूर को अभिनय की कला विरासत में मिली। उनके पिता रणधीर कपूर अभिनेता जबकि मां बबीता और बहन करिशमा कपूर जानी मानी फिल्म अभिनेत्री थीं। घर में फिल्मी माहौल रहने के कारण करीना अक्सर अपनी बहन के साथ शूटिंग देखने जाया करती थीं। इस वजह से उनका भी रूझान फिल्मों की ओर हो गया और वह भी अभिनेत्री बनने के ख्वाब देखने लगीं।

करीना कपूर ने बतौर अभिनेत्री अपने सिने करियर की शुरूआत वर्ष 2000 में प्रदर्शित फिल्म रिफ्यूजी से की। इस फिल्म में उनके नायक की भूमिका अभिषेक बच्चन ने निभायी थी जो उनकी भी पहली फिल्म थी। हालांकि फिल्म टिकट खिड़की पर कोई खास कमाल नही दिखा सकी। वर्ष 2001 में प्रदर्शित फिल्म मुझे कुछ कहना है करीना के करियर की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। वर्ष 2001 में करीना को सुभाष घई की फिल्म यादें में काम करने का अवसर मिला लेकिन कमजोर पटकथा के कारण यह फिल्म टिकट खिड़की पर औंधे मुंह गिर गई। हालांकि उस वर्ष उनकी कभी खुशी कभी गम और अजनबी. जैसी सुपरहिट फिल्में भी प्रदर्शित हुई लेकिन कामयाबी का श्रेय इन फिल्मों के अभिनेताओं को अधिक दिया गया।

वर्ष 2002 में करीना कपूर के करियर के लिए महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष उनकी जीना सिर्फ मेरे लिए और मुझसे दोस्ती करोगे जैसी हिट फिल्में प्रदर्शित हुईं। वर्ष 2003 में करीना को सूरज बड़ज़ात्या की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म में ऋतिक रौशन और अभिषेक बच्चन जैसे सितारे थे बावजूद यह फिल्म टिकट खिड़की पर कोई खास कमाल नही दिखा सकी। वर्ष 2004 में करीना के अभिनय के नये आयाम देखने को मिले। इस वर्ष करीना की युवा, चमेली, हलचल और एतराज जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुयी। सुधीर मिश्रा के निर्देशन में बनी फिल्म चमेली में करीना ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिये उन्हें फिल्म फेयर का पुरस्कार भी दिया गया।वर्ष 2006 में करीना कपूर की सुपरहिट फिल्म ओंकारा प्रदर्शित हुई।

विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म ओंकारा में करीना को उनके दमदार अभिनय के लिए फिल्मफेयर की ओर से क्रिटिक्स अवार्ड द्वारा गया। इसी वर्ष प्रदर्शित फिल्म डॉन में करीना कपूर ने कैमियो किया। इस फिल्म में करीना ने हेलन के सुपरहिट गाने ये मेरा दिल यार का दीवाना पर डांस कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वर्ष 2007 में प्रदर्शित फिल्म जब वी मेट करीना कपूर के करियर की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में करीना के अपोजिट शाहिद कपूर थे। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इस फिल्म के लिए करीना कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2008 में करीना कपूर की सुपरहिट फिल्म गोलमाल रिटर्नस प्रदर्शित हुई। वर्ष 2009 में प्रदर्शित फिल्म थ्री इडियटस करीना कपूर के करियर की सुपरहिट फिल्मों में शुमार की जाती है। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में करीना कपूर के अपोजिट आमिर खान थे। थ्री इडियट बॉलीवुड के इतिहास में 200 करोड़ रूपये की कमाई करने वाली पहली फिल्म थी।

वर्ष 2010 में प्रदर्शित और रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म गोलमाल 3 के लिए करीना कपूर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित की गयी। वर्ष 2011 में प्रदर्शित फिल्म बाडीगार्ड करीना के करियर की सर्वाधिक कामयाब फिल्मों में शुमार की जाती है। करीना और सलमान की जोड़ी को बाडीगार्ड में काफी पसंद किया गया। वर्ष 2011 में करीना कपूर को शाहरूख खान के साथ रा.वन में काम करने का अवसर मिला। अनुभव सिन्हा के निर्देशन बनी इस फिल्म में करीना कपूर पर फिल्माया गाना छम्मक छल्लो बेहद लोकप्रिय हुआ था। वर्ष 2012 में प्रदर्शित फिल्म हीरोइन हालांकि टिकट खिड़की पर कामयाब नही हो सकी लेकिन उनके अभिनय को दर्शकों ने बेहद पसंद किया।

करीना कपूर ने वर्ष 2012 में सैफ अली खान से शादी कर ली। वर्ष 2013 में करीना कपूर की गोरी तेरे प्यार में और सत्याग्रह जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल नही दिखा सकी। वर्ष 2014 में करीना की सिंघम रिटनर्स. प्रदर्शित हुई है और इसने टिकट खिड़की पर 140 करोड़ रूपये की कमाई की।वर्ष 2015 में करीना की फिल्म बजरंगी भाइजान प्रदर्शित हुयी। फिल्म ने टिकट खिड़की पर 320 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इसके बाद करीना ने की एंड का ,उड़ता पंजाब,वीरे दी वेडिंग,गुड न्यूज और अंग्रेजी मीडियम जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। वर्ष 2022 में करीना कपूर फिल्म लाल सिंह चड्ढा प्रदर्शित हुयी। करीना की आने वाली फिल्मों में जानेजान और द क्रू प्रमुख है।

झक्कास-बोलने से पहले लेनी पड़ेगी अनिल कपूर की इजाजत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बालीवुड अभिनेता अनिल कपूर के पर्सनलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए उनकी सहमति के बिना उनके नाम, इमेज या आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यहां तक कि उनके फेमस डायलॉग झक्कास के इस्तेमाल से पहले भी अभिनेता से इजाजत लेने को कहा गया है। अनिल कपूर ने हाल ही में अपनी पर्सनलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में एक्टर ने अलग-अलग संस्थाओं को बिना उनकी सहमति के उनका नाम, आवाज, इमेजिस और निक नेम का उपयोग करने पर रोक लगाने की मांग की थी।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि किसी शख्स के नाम, आवाज, इमेज या फिर डायलॉग को अवैध तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किसी सेलेब को एंडोर्स करने पर कई लोगों की आजीविका निर्भर करती है, इसे अवैध रूप से इस्तेमाल करने की अनुमति देकर खराब नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कई लोग दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं।

सेलिब्रिटीज को भी अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का अधिकार है। लोगों के इस तरह के वीडियो वायरल करने पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्मेंट को सभी लिंक तुरंत हटाने के भी निर्देश दिए हैं।

25 साल बाद फिर करण जौहर के साथ सलमान खान

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान फिल्मकार करण जौहर की फिल्म में काम करते नजर आ सकते हैं। सलमान खान ने करण जौहर की फिल्म कुछ-कुछ होता है में काम किया था। 25 साल बाद एक बार फिर से सलमान खान, करण जौहर की अनटाइटल फिल्म में काम करते नजर आ सकते हैं। इस फिल्म का निर्देशन विष्णुवर्धन करेंगे।

सलमान की फिल्म टाइगर 3 दीवाली के मौके पर रिलीज हो रही है। इसके अलावा वह जल्द ही बिग बॉस 17 की शूटिंग भी शुरू करेंगे। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अलावा सलमान खान, करण जौहर की फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे, जिसकी तैयारियां सलमान खान के शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट, स्क्रीनप्ले, डायलॉग ड्राफ्ट सब फाइनल हो चुके हैं। सलमान खान इस अनटाइटल फिल्म का फर्स्ट हाफ दिसंबर में शूट करेंगे और बाकी का बचा हुआ वह जनवरी में शूट करेंगे। इंडियन आर्मी के बैकड्राप पर बनने वाली इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट तृषा, सामंथा या अनुष्का शेट्टी में से एक अभिनेत्री नजर आ सकती है।

Guru Nanak Dev Death Anniversary

सिखों के पहले गुरु थे नानक देव, समाजिक कुरीतियों को खत्म करने में निभाई अहम भूमिका

अनन्या मिश्रा

सिखों के पहले गुरु, गुरु नानक देव को सिख धर्म के लोग नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और नानकशाह नामों से भी पुकारते हैं। नानक जी के व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्मसुधारक, समाजसुधारक, कवि, देशभक्त और विश्वबन्धु सभी के गुण मौजूद थे। बता दें कि आज ही के दिन यानी की 22 सितंबर को गुरु नानक देव जी ने अपनी देह का त्याग कर दिया था। आइए जानते हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में...

जन्म-गुरु नानक देव जी का जन्म पाकिस्तान (पंजाब) में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। सिख धर्म में इस दिन को काफी उल्लास के साथ मनाया जाता है। नानक जी के पिता का नाम कल्याण या कालू मेहता और मां का नाम तृप्ती देवी था। नानक जी ने हिंदू परिवार में जन्म लिया था। नानक देव जी बचपन से ही विशेष शक्तियों के गुणी थे। नानक जी ने अपनी बहन नानकी से काफी कुछ सीखा।

वहीं महज 16 साल की उम्र में नानक देव का विवाह सुलक्खनी से हो गया। इनके दो पुत्र श्रीचंद और लख्मी चंद थे। वहीं बच्चों के जन्म के कुछ समय बाद ही नानक देव जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। इस दौरान उन्होंने काफी लंबी यात्राएं की। इस दौरान नानक देव दी मरदाना, लहना, बाला और रामदास भी गए। साल 1521 तक यात्रा के दौरान वह सबको उपदेश देते रहे। साथ ही समाज में फैली कुरीतियों के प्रति भी लोगों को जागरुक करते रहे। इसके अलावा नानक देव जी ने भारत, अफगानिस्तान और अरब के कई स्थानों का भ्रमण किया। गुरु नानक देव की इन यात्राओं को सिख धर्म में उदासियां भी कहा जाता है।

लंगर की शुरुआत

युवावस्था में आने के बाद एक दिन नानक देव जी के पिता ने उन्हें 20 रुपए देकर व्यापार करने के लिए भेजा। रास्ते में नानक देव जी को कुछ भूखे साधु मिल गए। इसके बाद नानक देव जी उन साधुओं को लेकर नजदीक के एक गांव में ले गए और उन्हें 20 रुपए में भरपेट खाना खिलाया। तब से गुरु नानक देव जी द्वारा 20 रुपए से लंगर की रीत शुरू हुई, जो आजतक चल रही है।

नानक देव जी का संदेश

बता दें कि 15वीं शताब्दी के दौरान जब भारत आक्रांताओं के हमले को झेल रहा था। आक्रमणकारियों में भारत की संपदा लूटने की होड़ मची थी। उस दौरान लोग बुरा से बुरा काम करने से भी पीछे नहीं हटते थे। तब नानक देव जी ने भारत में वंड छको का संदेश देकर ऊंच नीच, बड़े छोटे, अमीर गरीब के भेदभाव को खत्म करने में अपनी अहम भूमिका निभाई।

सिख धर्म की उत्पत्ति

5 शताब्दी पहले सिख धर्म की उत्पत्ति गुरु नानक देव जी ने की थी।। नानक जी जहां हिंदु परिवार से ताल्लुक रखते थे, तो वहीं मुस्लिम पड़ोसियों के बीच बड़े हुए थे। कम उम्र से ही नानक देव में गहरी आध्यात्मिकता दिखाई देने लगी थी। उन्होंने धार्मिक परंपराओं से खुद को दूर करते हुए ईश्वर के प्रति अपना ध्यान लगाया। उन्होंने मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया। सिख धर्म के पहले गुरु गुरुनानक देवी जी के चार शिष्य हुए। वह चारों शिष्य नानक देव जी के साथ रहते थे। उन्होंने अपनी हर उदासी इन शिष्यों के साथ की। नानक देव जी ने 60 से ज्यादा शहरों का भ्रमण किया और वह मक्का की यात्रा पर भी गए थे।

नानक देव जी की मक्का यात्रा

बताया जाता है कि जब नानक देव मक्का गए तो पवित्र स्थान की ओर पैर करके सो गए। इससे नाराज लोगों ने उनसे अपने पैर दूसरी दिशा में रखने को कहा। इस पर नानक देव ने कहा कि वह बहुत थके हैं, ऐसे में जिधर मक्का ना हो, वह उनके पैर उधर घुमा दें। तब लोगों को गुरु नानक देव जी का संदेश समझ आया कि ईश्वर हर कहीं विद्यमान हैं।